राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरांचल, उतराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 04 नवंबर 2026 वर्ष-9,अंक-274 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पंजाब में अकाली-बीजेपी गठबंधन लगभग तय!

- दीवाली के बाद लगेगी मुहर दोनों पार्टियां हैं तैयार

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस बीच दोनों पूर्व एनडीए सहयोगियों के बीच गठबंधन पर अंतिम फैसला दीवाली के आसपास होने की उम्मीद



है। पीएम मोदी खुद इस गठबंधन को लेकर ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि इस घोषणा को एक ऐतिहासिक रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बठिंडा में एक विशाल रैली कराने की तैयारी भी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस रैली में पीएम मोदी अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर ऐलान कर सकते हैं। हालांकि, सीटों के बंटवारे को लेकर अभी अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है। सूत्रों की मानें तो बीजेपी 45 से 50 सीटों पर समझौता कर सकती है।

अमित शाह से मिले चिरंजीवी व राम चरण

- बोले-एआई और डीपफेक तकनीक से कलाकारों को खतरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी और उनके बेटे राम चरण ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों कलाकारों ने फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल



इंटेलिजेंस और डीपफेक तकनीक के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई। चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस मुलाकात की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए सरकार की ओर से सख्त नियम और कड़े दंड का प्रावधान करने का आश्वासन दिया। साथ ही लिखित आवेदन जमा करने की सलाह दी।

त्रिपुरा में बीएसएफ जवानों पर तस्करों ने किया हमला

- 3 घायल, अब तक 8 गिरफ्तार ढाई साल में ऐसी 3 घटनाएं



अगरतला (एजेंसी)। त्रिपुरा के आशाबाड़ी बॉर्डर आउटपोस्ट के पास सोमवार को कुछ तस्कर अवैध सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान बीएसएफ की 49वीं बटालियन के जवानों ने उनका पीछा किया और एक संदिग्ध को पकड़ लिया। उसकी पहचान हिफजुर रहमान के रूप में हुई है। इसी दौरान रहीमपुर कांतामुरा बॉर्डर आउटपोस्ट से बीएसएफ के 3 जवान गाड़ी से बॉक्सानगर जा रहे थे। रास्ते में तस्करों के एक समूह ने उन्हें घेरकर हमला कर दिया। हमलावरों ने जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएम माणिक साहा ने घटना की निंदा की है और आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, हमारा अखबार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। त्रिपुरा में इस घटना के साथ बीएसएफ जवानों पर हमले की 3 घटनाएं हो चुकी हैं। अप्रैल 2024 में दुर्गापुर गांव में तस्करी रोकने पर भीड़ ने जवानों पर हमला किया था, जिसमें 3 जवान घायल हुए थे। वहीं, नवंबर 2025 में बिशालगढ़ में संदिग्ध पशु तस्करों को रोकने पर भीड़ ने बीएसएफ की गाड़ी में तोड़फोड़ की थी।

एक जगह अनिश्चितकाल तक धरना नहीं दे सकते

सुप्रीम कोर्ट बोला-प्रदर्शन एक का नहीं,सबका अधिकार

कहा-रोजगार और कारोबार का ध्यान रखना भी है जरूरी

- दिल्ली में हुए प्रदर्शनों को लेकर सीजेआई की सख्त टिप्पणी



नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों, लोगों को बड़ी संख्या में हिरासत में लेने, पुलिस की बर्बरता, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ व्यापारियों की याचिकाओं पर आज मंगलवार को सुनवाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, आप किसी जगह पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते।

अन्य प्रदर्शनकारी भी हैं। किसान या वकील कहां जाएंगे। हर किसी को विरोध करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी पिछले महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विपक्षी दलों और अन्य लोगों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ किए गए बड़े विरोध प्रदर्शन की सुनवाई के दौरान आई, जब उस जगह से विरोध प्रदर्शन स्थल का दर्जा हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में व्यापारिक संगठनों ने याचिका दायर की, जिसमें बताया कि विरोध प्रदर्शनों की वजह से उनका काफी नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने व्यापारियों के संगठनों से कहा है कि वे एंटी-सरकार विरोध प्रदर्शन के आयोजकों को भी अपनी याचिका में पक्षकार बनाएं। विरोध प्रदर्शन के चलते व्यापारियों की स्थिति बताते हुए उनके वकील ने कोर्ट से कहा, विरोध स्थल के आस-पास के इलाकों में 50 लाख लोग रहते हैं। सभी दुकानें बंद हैं और आज कनॉट प्लेस में कोई नहीं है।

सरकार के शीर्ष वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो कोई भी विरोध प्रदर्शन का आह्वान करता है, उसे अपने कार्यों के नतीजों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।

व्यापारियों ने कहा-त्योहारों में 2000 करोड़ का नुकसान

सुनवाई के दौरान दिल्ली के व्यापारिक संगठनों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि प्रदर्शनों के कारण दिल्ली में कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। त्योहारों के सीजन में दुकानें बंद रहीं और बिक्री घट गई। उन्होंने दावा किया कि कारोबारियों को करीब 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर त्योहारों के सीजन में बिक्री नहीं होगी तो व्यापारियों और उनसे जुड़े लोगों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कोर्ट से अगले दो महीने तक किसी भी तरह के प्रदर्शन या धरने पर रोक लगाने की मांग की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की ओर से कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए सिर्फ एक दिन की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी 17 दिन तक वहां बैठे रहे। मेहता ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति संसद की ओर मार्च भी किया। संसद देश की संप्रभुता का प्रतीक है। बिना अनुमति संसद या सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जो संगठन बंद या प्रदर्शन का आह्वान करता है, उसे उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।

मोदी बोले-पहले गरीबी खत्म करने के वादे होते थे,अब जमीनी स्तर पर काम हो रहा

छोटे शहरों को भी विकास के केंद्र के रूप में तैयार करना होगा



नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कई पीढ़ियों ने गरीबी खत्म करने के वादे सुने हैं। पहले गरीबी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ नारों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे खत्म करने के लिए जमीन पर काम हो रहा है। उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे मेट्रो की करीब 21,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। आज दुनिया में भारत की चर्चा दो और वजहों से हो रही है। पहली, दुनिया में मुश्किल हालात के बावजूद भारत सबसे तेज आर्थिक विकास करने वाला देश बना हुआ है। दूसरी, सिर्फ 10 से 12 साल में भारत के 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है।

महाराष्ट्र में खराब मौसम से कई किसान परेशान हैं

महाराष्ट्र में खराब मौसम से कई किसान परेशान हैं। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में जल संरक्षण के लिए काम हुआ है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से किसानों को नुकसान हुआ है। इस मुश्किल समय में एनडीए सरकार किसानों की हर संभव मदद करेगी। देश के सैकड़ों छोटे शहरों को भी विकास के केंद्र के रूप में तैयार करना होगा। इसी सोच के साथ इस साल फरवरी में अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी गई थी। केंद्र सरकार इस फंड के लिए 1 लाख करोड़ की मदद दे रही है। पुणे मेट्रो लाइन का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी से हुआ है।

अग्निवीरों के पहले बैच को एक्सटेंशन दे सकती है सरकार

21 नवंबर को खत्म होगा कार्यकाल,दिल्ली में हुई कई हाईलेवल बैठकें



नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार पहले बैच के कुछ अग्निवीरों की चार साल की सेवा पूरी होने के बाद एक्सटेंशन देने पर विचार कर रही है। यह उन अग्निवीरों के अलावा होगा, जिन्हें स्थायी रूप से सेना में शामिल किया जाएगा। पहले बैच की चार साल की सेवा 21 नवंबर को खत्म होगी। इससे पहले स्थायी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और एक्सटेंशन के प्रस्ताव पर फैसला होने की उम्मीद है। सोमवार को सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर पिछले कुछ दिनों में कई हाईलेवल बैठकें हो चुकी हैं। अभी सरकार ने कोई फैसला घोषित नहीं किया है। प्रस्तावित एक्सटेंशन कितने समय का होगा, यह अभी साफ नहीं है। अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई थी। इसके तहत तीनों सेनाओं के अन्य रैंक में युवाओं की चार साल के लिए भर्ती की जाती है।

जेन-जी आंदोलन पर सुनील आंबेकर बोले-देशहित में होना चाहिए

आरएसएस के 3 साल का एजेंडा तय, 5 मुद्दों पर फोकस



इंदौर (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले तीन साल सामाजिक समरसता, पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली, कुटुंब प्रबोधन, स्व का भाव और नागरिक कर्तव्य जैसे पांच विषयों पर फोकस करेगा। संघ ने इन्हें पंच परिवर्तन नाम दिया है। शताब्दी वर्ष के दौरान इन विषयों को समाज तक पहुंचाने के लिए गृह संपर्क अभियान, सम्मेलन और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर में सोमवार को शुरू हुई अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की तीन दिवसीय बैठक में इन कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना पर मंथन हुआ। बैठक के बाद अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने जेन-जी आंदोलन से जुड़े सवाल पर कहा कि देश में कोई आवाज उठाता है तो संघ को पक्ष-विपक्ष के नजरिए से क्यों देखा जाता है। उन्होंने कहा कि सभी को ध्यान रखना चाहिए कि आंदोलन देशहित में हो। संघ इस विषय में सतर्क रहता है और आगे भी रहेगा।

महिलाओं और युवाओं को जोड़ने पर चर्चा

शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी रही। बैठक में इस अनुभव के आधार पर महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रमों और उपक्रमों पर विचार किया गया। युवाओं को जोड़ने के लिए शहरों, गांवों और कॉलेज कैंपस में आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। इनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और अन्य युवाओं ने हिस्सा लिया था। बैठक के एजेंडे में युवाओं में नशीली दवाओं के बढ़ते चलन पर चिंता और इससे निपटने के प्रयास भी शामिल रहे। आंबेकर ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर प्रयास जरूरी हैं।

देशभर में 1.01 लाख से ज्यादा दैनिक शाखाएं

आंबेकर के मुताबिक, देशभर में संघ की दैनिक शाखाओं की संख्या बढ़कर 1 लाख 1 हजार 151 हो गई है। साप्ताहिक और मासिक मिलन को मिलाकर संघ का काम 1 लाख 10 हजार 849 स्थानों तक पहुंच गया है। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में शताब्दी वर्ष के दौरान 13 हजार से अधिक नई दैनिक शाखाएं जुड़ी हैं। बैठक में शाखाओं के विस्तार के प्रयासों और उनके परिणामों की समीक्षा की गई। शाखाओं के साथ साप्ताहिक और मासिक मिलन की गतिविधियों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। शताब्दी वर्ष के दौरान देशभर में 65 हजार 660 हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

होर्मुज में भारतीय जहाज पर हमला, एक की मौत

14 भारतीय सवार थे,13 इंडियनों को बचाया गया



ओमान (एजेंसी)। होर्मुज स्ट्रेट में 2 नवंबर को एक भारतीय जहाज पर हमला हुआ। इसमें गुजरात के एक नाविक की मौत हो गई। जहाज पर सवार बाकी 13 भारतीयों को ओमान के कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया। मृतक की पहचान गांधार नाहीम अजीज के रूप में हुई है। जहाज का नाम अल जुसुफी है। हमला कैसे हुआ और किसने किया इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही और कारोबार बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक, इस साल अक्टूबर में होर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास जहाजों पर 30 से ज्यादा हमले हुए। ईरान-अमेरिका जंग शुरू होने के बाद एक महीने में हमलों की यह सबसे बड़ी संख्या थी।

पहले भी भारतीय नाविकों वाले जहाज पर हमला हुआ था

होर्मुज स्ट्रेट में इससे पहले 29 अक्टूबर को भारतीय नाविकों वाले जहाज को निशाना बनाया गया था। 27 भारतीय क्रू सदस्यों वाले तेल टैंकर लुईस 1 पर हमला हुआ था। पनामा के झंडे वाले इस जहाज के पास एक छोटी नाव आई थी। उसमें सवार लोगों ने जहाज के बाहरी हिस्से पर दो विस्फोटक चिपका दिए थे और वहां से चले गए। कुछ देर बाद दोनों विस्फोटकों में धमाका हुआ। इससे जहाज के इंजन रूम में आग लग गई और इंजन कुछ समय के लिए बंद हो गया। हालांकि, क्रू ने आग पर काबू पा लिया।

इंडियन नेवी ने लुटेरों से ईरानी जहाज को बचाया



सोमालिया के लुटेरों ने क्रू के 20 लोगों का अपहरण किया था

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय नौसेना ने सोमाली समुद्री लुटेरों के कब्जे से मछली पकड़ने वाला जहाज अजिनी छुड़ा लिया। नौसेना ने जहाज के 20 ईरानी क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचाया। यह ऑपरेशन सोमवार को पूरा हुआ। 12 हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने गुरुवार को सोमालिया के उत्तर-पूर्वी तट जहाज का अपहरण किया था। मुंबई से 3,000 किमी से ज्यादा दूर चले 48 घंटे के ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने भी मदद की। भारतीय नौसेना ने अजिनी को खोजकर रोका। इसके बाद जहाज और उसके क्रू को समुद्री लुटेरों से छुड़ाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना को सफल ऑपरेशन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने समय पर मदद की। आशंका थी कि लुटेरे इसका इस्तेमाल व्यापारिक जहाजों पर आगे हमले करने के लिए करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, अपहरण के समय जहाज पर 21 ईरानी क्रू सदस्य और दो सोमाली सुरक्षा गार्ड थे। इस तरह जहाज पर कुल 23 लोग सवार थे। अजिनी का अपहरण अदन की खाड़ी और पश्चिमी हिंद महासागर में सोमाली समुद्री लूट की घटनाएं बढ़ने के बीच हुआ। हाल के महीनों में कई व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए हैं।

मुंबई से 3000 किमी दूर ऑपरेशन, 48 घंटे चला ऑपरेशन

श्रीनगर से सांसद मेहंदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी

जनसभा में सांसद पद से इस्तीफे का किया ऐलान



श्रीनगर (एजेंसी)। नेशनल कॉन्फ्रेंस से श्रीनगर के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहंदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संसद की सदस्यता भी छोड़ने का ऐलान किया। मंगलवार को बडगाम में जनसभा करके उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए। रूहुल्लाह ने कहा- यह आजादी का फैसला है। मैं एक शहीद की विरासत और पाक खून की नस्ल का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं अपनी आजादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आज दोपहर 2.40 बजे से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं हूं। उन्होंने बडगाम में पिता आगा सैयद मेहंदी की 26वीं पुण्यतिथि पर जनसभा बुलाई थी। रूहुल्लाह ने बताया कि वे अपना इस्तीफा मुहम्मद अशरफ मट्टू के जरिए पार्टी को भेजेंगे। उन्होंने पार्टी पर लोगों की गरिमा से समझौता करने का आरोप लगाया।

- 24 विधायक भी पार्टी छोड़ने की धमकी दे चुके हैं

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मन की शांति में ही जीवन की सच्ची समृद्धि

हमारी त्योहार संस्कृति भी तनाव के विरुद्ध एक सुंदर सामाजिक एवं सांस्कृतिक औषधि है। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकल्प देती है। होली मन के पुराने विकारों और कटु स्मृतियों को रंगों में बहाकर संबंधों में नई आत्मीयता भरने का अवसर देती है। रक्षाबंधन रिश्तों की सुरक्षा और विश्वास का उत्सव है। ईद भाईचारे, सेवा और साझी खुशियों का संदेश देती है, तो क्रिसमस प्रेम, करुणा और क्षमा की प्रेरणा देता है। पर्युषण पर्व आत्मशुद्धि, क्षमाभाव, संयम और आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। विशेषकर क्षमापना का भाव मनुष्य के भीतर वर्षों से संचित कटुता और प्रतिशोध की गांठें खोल सकता है। त्योहारों का वास्तविक आनंद तभी है जब वे केवल बाहरी सजावट और खर्च तक सीमित न रहकर मनुष्यों को मनुष्यों के करीब लाएं।

(लेखक- ललित गर्ग)

(अंतर्राष्ट्रीय तनाव जागरूकता दिवस (4 नवंबर 2026) पर विशेष)

जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य ने संसार को सुविधाओं से भर दिया, लेकिन स्वयं के भीतर सुकून के लिए जगह कम कर ली। आज हमारे पास समय बचाने के असंख्य साधन हैं, पर समय का अभाव है, संवाद के अनगिनत माध्यम हैं, पर आत्मीयता का अकाल है, भौतिक समृद्धि के नए प्रतिमान हैं, लेकिन मानसिक शांति निरंतर दूर होती जा रही है। आधुनिक मनुष्य की इस विरोधाभासी स्थिति का सबसे बड़ा नाम है-तनाव। तनाव अब केवल मन की बेचैनी नहीं, बल्कि हमारे समय की एक गंभीर सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और वैश्विक चुनौती बन चुका है। इसी चुनौती के प्रति चेतना जगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तनाव जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इसकी थीम है-''तनाव-मुक्ति और कल्याण के भविष्य को आकार देना तथा कार्यस्थल को फिर से मानवीय बनाना।'' यह विषय हमें याद दिलाता है कि कार्यस्थल केवल उत्पादन और उपलब्धियों का केंद्र नहीं, बल्कि मनुष्य की संवेदनाओं, गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य का भी स्थान होना चाहिए। आज का मनुष्य सुबह आंख खुलने से लेकर रात आंख बंद होने तक एक अदृश्य दौड़ में शामिल है। नौकरी की असुरक्षा, व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा, आर्थिक अपेक्षाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, बच्चों की शिक्षा, युवाओं के भविष्य की चिंता, बुजुर्गों का अकेलापन और सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने का दबाव उसके मन को लगातार मथता रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में अंक और प्रतियोगिता बच्चों के बचपन पर भारी पड़ रहे हैं। कार्यस्थलों पर लक्ष्य, समय-सीमा और प्रदर्शन का दबाव व्यक्ति को मशीन में बदलने लगा है। परिवारों में संवाद की जगह मोबाइल ने और आत्मीयता की जगह औपचारिकताओं ने ले ली है।

इस व्यक्तिगत तनाव के ऊपर वैश्विक परिस्थितियों का बोझ भी कम नहीं है। युद्ध, आतंकवाद, हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं की खबरें मनुष्य के भीतर भय और असुरक्षा का वातावरण निर्मित करती हैं। दुनिया के किसी कोने में होने वाला संघर्ष अब केवल उस क्षेत्र की समस्या नहीं रहता, बल्कि संचार माध्यमों के कारण पूरी मानवता की सामूहिक चिंता बन जाता है। इस प्रकार तनाव की सीमाएं घर की चारदीवारी से निकलकर राष्ट्रों और महाद्वीपों तक फैल गई हैं। तनाव को यदि समय रहते समझा और नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह शरीर और मन दोनों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। लगातार तनाव से नींद में गड़बड़ी, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याएं, पाचन संबंधी परेशानियां, चिड़चिड़ापन, अवसाद और एकाग्रता में कमी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तनाव मनुष्य की निर्णय क्षमता को कमजोर करता है और उसके संबंधों में कटुता घोल देता है। कहावत है-'चिंता चिता समान है।' यह केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि जीवन का गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। चिंता भविष्य की अनिश्चितताओं को वर्तमान की खुशियों पर हावी कर देती है। इसलिए तनाव से मुक्ति का पहला कदम है-अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना, समस्याओं को पहचानना और उनके समाधान की दिशा में विवेकपूर्ण प्रयास करना। इस संदर्भ में जैन धर्म के महान आध्यात्मिक आचार्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा विकसित एवं व्यवस्थित की गई प्रेक्षाध्यान पद्धति तनावमुक्त जीवन का एक अत्यंत प्रभावशाली मार्ग प्रस्तुत करती है। प्रेक्षाध्यान का मूल भाव है-देखना, जागरूक होकर देखना और अपने भीतर घटित होने वाली प्रक्रियाओं को निष्पक्ष भाव से समझना। यह केवल आंखें बंद करके बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं से साक्षात्कार करने की वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक साधना है। आचार्य महाप्रज्ञ ने ध्यान, श्वास-प्रेक्षा, शरीर-प्रेक्षा, चौतन्य-केंद्र प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा जैसे प्रयोगों के माध्यम से मनुष्य को अपने मन, शरीर और भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा दी।

प्रेक्षाध्यान का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है-भावनात्मक संतुलन। क्रोध, भय, ईर्ष्या, आवेश और निराशा जैसी वृत्तियों को पहचानकर उनके परिष्कार का प्रयास करना तनाव प्रबंधन की दिशा में सार्थक कदम है। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट का नियमित ध्यान, श्वास पर एकाग्रता और आत्मनिरीक्षण व्यक्ति के जीवन में धैर्य, सहनशीलता तथा मानसिक स्थिरता विकसित कर सकते हैं। इस साधना का संदेश है कि परिस्थितियों को हमेशा बदलना संभव नहीं, लेकिन परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदलना हमारे हाथ में है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा भी तनावमुक्त जीवन का अनमोल दर्शन प्रस्तुत करती है। उपनिषदों का आत्मबोध, गीता का निष्काम कर्मयोग, भगवान महावीर का समता दर्शन, भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग और पतंजलि का अष्टांग योग मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाने की प्रेरणा देते हैं। गीता का संदेश है-कर्म करो, फल की चिंता में स्वयं को मत उलझाओ। इसका अर्थ कर्म से पलायन नहीं, बल्कि परिणाम के अनावश्यक भय से मुक्त होकर पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। योग, प्राणायाम, ध्यान, मौन, स्वाध्याय और नियमित दिनचर्या मनुष्य को मानसिक संतुलन प्रदान करने के प्रभावी माध्यम हैं।

हमारी त्योहार संस्कृति भी तनाव के विरुद्ध एक सुंदर सामाजिक एवं सांस्कृतिक औषधि है। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकल्प देती है। होली मन के पुराने विकारों और कटु स्मृतियों को रंगों में बहाकर संबंधों में नई आत्मीयता भरने का अवसर देती है। रक्षाबंधन रिश्तों की सुरक्षा और विश्वास का उत्सव है। ईद भाईचारे, सेवा और साझी खुशियों का संदेश देती है, तो क्रिसमस प्रेम, करुणा और क्षमा की प्रेरणा देता है। पर्युषण पर्व आत्मशुद्धि, क्षमाभाव, संयम और आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। विशेषकर क्षमापना का भाव मनुष्य के भीतर वर्षों से संचित कटुता और प्रतिशोध की गांठें खोल सकता है। त्योहारों का वास्तविक आनंद तभी है जब वे केवल बाहरी सजावट और खर्च तक सीमित न रहकर मनुष्यों को मनुष्यों के करीब लाएं। सामूहिक उत्सव, पारिवारिक मिलन, लोकगीत, संगीत, सेवा और प्रकृति के साथ जुड़ाव जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। तनावमुक्त समाज के निर्माण में कार्यस्थलों, शिक्षण संस्थानों और परिवारों की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। कार्यालयों में मानवीय व्यवहार, काम और विश्राम के बीच संतुलन, सहकर्मियों के प्रति संवेदनशीलता तथा मानसिक स्वास्थ्य पर खुली बातचीत को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विद्यालयों में बच्चों की तुलना करने के बजाय उनकी प्रतिभा को समझना आवश्यक है। परिवारों में एक-दूसरे को सुनने, साथ बैठने और भावनाओं को साझा करने की संस्कृति विकसित करनी होगी। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, प्रकृति के सान्निध्य और डिजिटल माध्यमों के विवेकपूर्ण उपयोग को जीवनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। गंभीर या लगातार बने रहने वाले तनाव में मनोवैज्ञानिक अथवा योग्य चिकित्सक की सहायता लेने में भी संकोच नहीं करना चाहिए।

वस्तुतः तनाव से मुक्ति का अर्थ चुनौतियों से भागना नहीं, बल्कि चुनौतियों के बीच भी स्वयं को संभालकर रखना है। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, अपेक्षाएं जन्म लेती रहेंगी, लेकिन इन सबके बीच मनुष्य अपने भीतर शांति का एक ऐसा दीप जला सकता है, जिसकी रोशनी बाहरी अंधेरों से प्रभावित न हो। हमें समझना होगा कि सफलता का अर्थ केवल अधिक पाना नहीं, बल्कि जो प्राप्त है उसमें संतोष, संबंधों में मधुरता और मन में संतुलन बनाए रखना भी है। अंततः जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं कि हमने कितनी ऊंचाइयां छुईं, बल्कि इस बात में है कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए अपने भीतर की शांति कितनी बचाकर रखी। तनाव को जीवन का स्वामी नहीं, अपनी जागरूकता से नियंत्रित की जाने वाली स्थिति बनाना ही इस दिवस का वास्तविक संदेश है। आइए, हम ऐसी जीवनशैली और ऐसी सामाजिक संस्कृति का निर्माण करें, जहां प्रतिस्पर्धा से अधिक सहयोग, उपलब्धियों से अधिक आत्मीयता और भौतिक प्रगति से अधिक मानवीय संवेदनाओं का सम्मान हो। क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और शांतिपूर्ण विश्व की आधारशिला है।

संपादकीय

फिर हेलीकॉप्टर हादसा

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों को ला रहा एक हेलीकॉप्टर फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में बद्रीनाथ से देहरादून लौट रहे पांच तीर्थयात्रियों और पायलट समेत छह लोगों की मौत हो गई। जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के चलते पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर यात्रियों के बचने की संभावना ना के बराबर होती है। यदि राहत व बचाव का कार्य शुरू भी किया जाए तो विषम परिस्थितियों में यह संभव नहीं हो पाता। लेकिन बेहद ऊंचे हिमालयी इलाकों में हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर जो अतिरिक्त सुरक्षा सावधानी बरती जानी चाहिए, वह नजर नहीं आती। लगता हेलीकॉप्टर सेवा संचालित करने वाली कंपनियां यात्रियों की सुरक्षा के बजाय अपने मुनाफे को ही प्राथमिकता दे रही हैं। विडंबना यह है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान ऐसे हादसे लगातार होते रहे हैं। बल्कि हादसों के बाद कुछ समय के लिये हेलीकॉप्टर सेवाओं को रोका भी गया था। लेकिन फिर 'वही ढाक के तीन पात' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में इस हिमालयी राज्य में हेलीकाप्टर हादसे और इमरजेंसी की स्थिति में हेलीकॉप्टर उतारने की कई घटनाएं सामने आई हैं। जिसके चलते निजी कंपनियों द्वारा हवाई सेवा के परिचालन के तौर-तरीकों और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस बाबत गत वर्ष जुलाई में संसद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक जानकारी संसद को दी गई थी। जिसमें बताया गया कि साल 2020 के बाद देश में बारह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इनमें से सात दुर्घटनाएं सिर्फ उत्तराखंड में हुई थीं। इन हादसों में जिन तीस लोगों की मृत्यु हुई, उनमें से इक्कीस सिर्फ उत्तराखंड में हुए हादसों में मारे गए। जिससे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में हवाई सेवा देने वाली कंपनी की सुरक्षा नीति और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठने स्वाभाविक ही हैं। इन हादसों के बाद हुए व्यापक विरोध के चलते कुछ समय हेलीकॉप्टर सेवा का परिचालन स्थगित भी किया गया था। यहां सवाल उठना स्वाभाविक है कि इन हादसों के बाद भी नियामक संस्थाएं तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी की जवाबदेही क्यों तय नहीं कर रही हैं? सवाल यह भी है कि तीर्थ यात्रियों का जीवन खतरे में डालने वाली कंपनी के मालिक व अधिकारियों को क्या कभी जवाबदेह ठहराया गया? क्या कंपनी पर कभी जुर्माना लगाया गया? बीच में सेवा को स्थगित किया था,तो क्या इस सेवा को फिर से शुरू करने के लिये सुरक्षा मानकों पर कंपनी खरी उतरी थी? यदि खरी उतरी थी तो यह नया हादसा कैसे हुआ? जाहिर है, इस हेलीकॉप्टर सेवा के दौरान सिर्फ कंपनी के मुनाफे को प्राथमिकता दी जा रही है। यह सर्वविदित है कि बद्रीनाथ व केदारनाथ आदि तीर्थ बेहद ऊंचाई पर स्थित हैं। जहां लगातार मौसम अचानक बदलता रहता है। मौसम खराब होने पर हवाई यात्रा जोखिमभरी होती है। जिसके चलते बदलते मौसम को लेकर भी सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर तीर्थयात्रियों का हादसे का शिकार होना, श्रद्धालुओं की आस्था व विश्वास को भी प्रभावित करता है।

विपक्षी हुंकार शक्ति-प्रदर्शन नहीं, जनकल्याण का कारण बने

(लेखक - ललित गर्ग)

लोकतंत्र केवल सत्ता परिवर्तन की व्यवस्था नहीं, बल्कि जनआकांक्षाओं, नागरिक अधिकारों, जवाबदेही और सार्थक राजनीतिक संवाद की जीवंत प्रणाली है। इसकी मजबूती केवल सत्तारूढ़ दल की कार्यक्षमता से नहीं, बल्कि विपक्ष की जिम्मेदारी, उसकी वैचारिक परिपक्वता और जनहित के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से भी निर्धारित होती है। लेकिन जब विपक्ष की राजनीति का केंद्र जनता के बुनियादी सवालों के बजाय सत्ता का विरोध, नेतृत्व पर व्यक्तिगत हमले और आरोपों की पुनरावृत्ति बन जाए, तब लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती को लेकर प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के नेतृत्व में लगभग बीस विपक्षी दलों का जुटना और वोट चोरी के मुद्दे पर हुंकार भरना इसी संदर्भ में राजनीतिक समीक्षा की अपेक्षा करता है। सवाल यह नहीं कि विपक्ष को रैली करने का अधिकार है या नहीं, बल्कि यह है कि ऐसी रैलियों से लोकतंत्र और आम जनता को आखिर क्या हासिल हो रहा है? रामलीला मैदान ऐतिहासिक रूप से जनआंदोलनों, राजनीतिक चेतना और लोकतांत्रिक प्रतिरोध का साक्षी रहा है। यहां उमड़ने वाली भीड़ को केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि उससे जुड़े संदेश और उद्देश्य का मूल्यांकन भी आवश्यक है। कांग्रेस ने सहयोगी दलों को एक मंच पर लाकर अपनी राजनीतिक एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रयास किया। दस लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया था, लेकिन उपलब्ध विवरणों के अनुसार वास्तविक उपस्थिति इस दावे से काफी कम रही। फिर भी इस आयोजन का महत्त्व केवल भीड़ के आकार से नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक संदेश से तय होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि इस रैली में भी विपक्ष की ओर से वही पुराने आरोप, वही राजनीतिक भाषण और वही सत्ता विरोधी तेवर अधिक दिखाई दिए, जिनकी पुनरावृत्ति लंबे समय से होती रही है।

वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर को लेकर विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का अधिकार ही नहीं, उसका दायित्व भी है। प्रत्येक वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहना चाहिए और किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आरोपों के साथ प्रमाण और तथ्यों की विश्वसनीयता भी आवश्यक है। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का प्रश्न उठाया जा रहा है, उनमें मृतक, स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाता भी शामिल बताए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने भी एसआईआर से जुड़े निर्णयों को तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिया गया बताया है। इस प्रक्रिया को लेकर न्यायालय में विचार और निर्देश भी सामने आए हैं। इसलिए इस पूरे विषय पर अंतिम निष्कर्ष तथ्यों, प्रमाणों और न्यायिक परीक्षण के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। विपक्ष का दायित्व है कि वह चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग करे, मतदाता सूची की त्रुटियों को उजागर करे और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस प्रयास करे। लेकिन केवल वोट चोरी का नारा बुलंद करने से लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास मजबूत नहीं होगा। यदि विपक्ष वास्तव में मतदाता अधिकारों को लेकर गंभीर है तो उसे प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने, मतदाता सूची की जांच करने, वास्तविक विसंगतियों के प्रमाण जुटाने और प्रभावित नागरिकों को न्याय दिलाने की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा नारों से कम और धरातल पर किए गए कार्यों से अधिक होती है। इस रैली का एक दूसरा पहलू भी है।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की राजनीतिक एकजुटता का आधार क्या है? क्या यह एकजुटता किसी साझा आर्थिक दृष्टि, रोजगार नीति, कृषि सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय के व्यापक कार्यक्रम पर आधारित है? अथवा इसका मुख्य उद्देश्य नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध करना और सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक वातावरण तैयार करना है? यदि किसी गठबंधन की एकता का सबसे बड़ा आधार किसी एक नेता या सरकार का विरोध हो, तो उसकी वैचारिक स्थिरता और भविष्य की दिशा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सत्ता विरोध अपने आप में कोई राजनीतिक दर्शन नहीं हो सकता।

लोकतंत्र में विपक्ष केवल आलोचक नहीं होता, वह वैकल्पिक नीतियों का निर्माता भी होता है। संसद में विधेयकों पर गंभीर चर्चा, सरकार की नीतियों का तथ्यात्मक परीक्षण, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर वैकल्पिक सुझाव तथा जनता की आवाज को संस्थागत मंचों तक पहुंचाना उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन जब राजनीतिक विमर्श आरोप-प्रत्यारोप, व्यक्तिगत कटाक्ष और विरोध प्रदर्शनों तक सीमित होने लगता है, तब जनता के वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। विपक्ष को यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री की आलोचना करना और प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में अपनी योग्यता प्रमाणित करना दो अलग-अलग बातें हैं। पहली बात राजनीतिक विरोध है, जबकि दूसरी लोकतांत्रिक नेतृत्व की कसौटी है। आज भारत अनेक बुनियादी चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार, किसानों की आय और कृषि की उत्पादकता, छोटे व्यापारियों की आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण, शहरी अव्यवस्था, बढ़ती आर्थिक विषमता और महिलाओं की सुरक्षा जैसे प्रश्न किसी एक दल के नहीं, पूरे राष्ट्र के प्रश्न हैं। क्या रामलीला मैदान की हुंकार इन विषयों पर कोई ठोस वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकी? क्या विपक्ष ने यह बताया कि वह इन समस्याओं के समाधान के लिए कौन-सी नीतियां अपनाएगा? क्या उसने देश के सामने कोई साझा विकास दृष्टि रखी? इन सवालों का उत्तर ही इस रैली की राजनीतिक सार्थकता का वास्तविक मूल्यांकन करेगा।

यह भी समझना आवश्यक है कि लोकतंत्र में भीड़ जुटाना और जनमत अर्जित करना अलग-अलग बातें हैं। भीड़ किसी क्षणिक राजनीतिक उत्तेजना, संगठनात्मक शक्ति अथवा विरोध की भावना से जुट सकती है, लेकिन स्थायी जनविश्वास विचारों, नीतियों, आचरण और परिणामों से अर्जित होता है। राजनीतिक दलों को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि विशाल मंच, बड़े भाषण और एकजुटता के प्रदर्शन से जनता का विश्वास स्वतः प्राप्त हो जाएगा। आज का मतदाता पहले की तुलना में अधिक जागरूक है। वह केवल यह नहीं सुनना चाहता कि सरकार ने क्या गलत किया, बल्कि यह भी जानना चाहता है कि विपक्ष उस स्थिति को सुधारने के लिए क्या करेगा। कांग्रेस के लिए यह आत्ममंथन का अवसर है।

गहराई में जाएं



गुरू के पास तीन शिष्य आए, बोले, गुरूदेव! हम साधना करना चाहते हैं। कोई साधना का सूत्र बताएं। गुरू ने सोचा, साधना का सूत्र बताने से पहले परीक्षा कर ली जाए। गुरू ने तीनों से एक प्रश्न पूछा, आंख और कान में कितना अंतर है। पहला व्यक्ति बोला, चार अंगुल का। दूसरे ने कहा, कान से आंख ज्यादा काम आती है। आंखों देखी बात बहुत स्पष्ट होती है। आंखों देखी और कानों सुनी बात में बहुत अंतर होता है। तीसरे का जवाब था, आंख से हम देख सकते हैं, किन्तु परमार्थ की बात कान से ही सुन सकते हैं।

गुरू ने पहले व्यक्ति से कहा, तुम अभी व्यापार करो। तुम्हारा नाप-जोख में रस है। तुम साधना के अधिकारी नहीं हो। दूसरे व्यक्ति से कहा, तुम अभी न्याय का काम करो। लोगों के झगड़े सुलझाओ। आंख द्वारा देखे गए प्रमाण ज्यादा सच होते हैं। तीसरे व्यक्ति से कहा, तुम साधना के योग्य हो। मैं तुम्हें आत्मिक ज्ञान दूंगा, क्योंकि तुम परमार्थ की बात में रस लेते हो।

यही कान, यही आंख सबके पास है। यदि आंख सच्चाई को देखने लग जाए, कान परमार्थ की बात को सुनने लग जाए तो नई बातें हमें प्राप्त हो सकती हैं। इसके लिए हमें गहराई में जाना होगा। सतह पर रहने से काम नहीं चलेगा। यदि हम अध्यात्म चिकित्सा या भाव चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग प्रस्तुत करें तो अध्यात्म की उपयोगिता बढ़ेगी, यह विश्वास प्रबल होता है। यह भौतिकता का नहीं, अध्यात्म का भी एक साम्राज्य है और उसके बिना मनुष्य सुख और शांति का जीवन जी नहीं सकता।

कर्ज की आंधी में बिखरते परिवार, बाजारवाद- सामाजिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल

(लेखक -सनत जैन)

भोपाल के मालीखेड़ी में नरेंद्र साहू (35) द्वारा अपनी मां, पत्नी और दो मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद स्वयं आत्महत्या कर लेने की हृदयविदारक घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के पीछे कर्ज का भारी बोझ, आर्थिक दबाव, कथित अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग जैसे कारण सामने आए हैं। बताया जाता है कि नरेंद्र पर इतना कर्ज था, वह प्रतिमाह लगभग 40 हजार रुपये ब्याज चुका रहा था। मकान, कार और बाइक बेचने के बाद भी वह कर्ज से मुक्त नहीं हो सका। अंततः उसने ऐसा भयावह कदम उठा लिया, जिसकी कीमत पूरे परिवार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यह घटना केवल एक व्यक्ति के अपराध या मानसिक तनाव की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते भारतीय समाज की उस तस्वीर को सामने लाती है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। सवाल यह है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? पिछले दो दशकों में भारत में कर्ज लेने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। बैंक, वित्तीय संस्थान, निजी फाइनेंस कंपनियां और सूदखोर आसानी से कर्ज उपलब्ध करा रहे हैं। मकान, वाहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों के लिए कर्ज लेना अब सामान्य बात हो गई है। समस्या तब शुरू होती है, जब व्यक्ति अपनी आमदनी से अधिक खर्च करने लगता है। दूसरों की जीवनशैली देखकर वैसी ही सुविधाएं जुटाने की होड़ में वह अपनी आर्थिक क्षमता को भूल जाता है। मोबाइल, महंगे वाहन, मकान, शादी-विवाह और सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर अनावश्यक खर्च बढ़ता चला जाता है। बाजारवाद ने हमारी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का अंतर लगभग समाप्त कर दिया है। विज्ञापन और आसान किस्तों का आकर्षण लोगों को यह विश्वास दिलाता है, आज ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, भुगतान बाद में हो जाएगा। नतीजा यह है कि कई परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा कर्ज की किस्तों और ब्याज में खर्च कर रहे हैं। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। धीरे-धीरे व्यक्ति कर्ज के ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है। सबसे चिंताजनक स्थिति तब पैदा होती है, जब बैंकिंग व्यवस्था से बाहर ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देने वाले सूदखोर आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाते हैं। किस्त नहीं चुका पाने के कारण बैंक का ब्याज भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जाता है। प्रताड़ना, धमकी, ब्लैकमेलिंग और लगातार वसूली का दबाव व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ देता है। हालांकि आर्थिक संकट किसी भी परिस्थिति में हत्या या आत्महत्या को उचित नहीं ठहरा सकता, ऐसी घटनाओं के पीछे मौजूद सामाजिक और आर्थिक कारणों को समझना जरूरी है। तभी इसका समाधान निकाला जा सकता है।

समस्या का समाधान केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार, सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं और वित्तीय संस्थान सभी को अपनी भूमिका तय करनी होगी। सबसे पहले स्कूलों और कॉलेजों में वित्तीय साक्षरता की शिक्षा दी जानी चाहिए, युवा पीढ़ी आमदनी, बचत, ब्याज और कर्ज के वास्तविक अर्थ को समझ सकें। परिवारों में दिखावे के बजाय बचत और आवश्यकता के अनुसार खर्च करने की संस्कृति विकसित करनी होगी। सरकार को अवैध सूदखोरी, बैंकों द्वारा कर्ज एनपीए होने पर जुर्माना ब्याज पर ब्याज वसूलने के नियमों को सरल बनाना होगा। गुंडागर्दी के बल पर कर्ज की वसूली को रोकने का कानून बनना होगा। कानून का पालन नहीं होने पर सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कर्ज में फंसे परिवारों के लिए परामर्श केंद्र, कानूनी सहायता और ऋण पुनर्गठन की व्यवस्था होनी चाहिए। बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को भी कर्ज देने से पहले व्यक्ति की वास्तविक भुगतान क्षमता का आकलन करना चाहिए। आर्थिक संकट से गुजर रहे, लोगों के लिए गोपनीय मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और सहायता की व्यवस्था भी जरूरी है। सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी विवाह, सामाजिक समारोह और पारिवारिक आयोजनों में फिजूलखर्ची रोकने के लिए अभियान चलाना चाहिए। समाज में प्रतिष्ठा का पैमाना महंगी गाड़ी, बड़ा मकान और ब्रांडेड सामान नहीं, बल्कि ईमानदार जीवन, आर्थिक आत्मनिर्भरता और पारिवारिक खुशहाली होना चाहिए। आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कर्ज लेकर जीने की संस्कृति सौंपना चाहते हैं, या उन्हें अपनी आमदनी में खुश रहना सिखाना चाहते हैं? आर्थिक विकास का अर्थ केवल बाजार में बढ़ती खरीदारी और बैंकों के बढ़ते कर्ज का आंकड़ा नहीं हो सकता। वास्तविक विकास वह है, जिसमें परिवार सुरक्षित हों, बच्चों का भविष्य बेहतर हो, परिवार में खुशी हो, किसी व्यक्ति को आर्थिक परेशानी के कारण जीवन समाप्त करने जैसा विचार न आए। पिछले कुछ वर्षों से इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। भोपाल की यह त्रासदी गंभीर चेतावनी है। समय रहते बाजारवाद, दिखावे और कर्ज की अंधी दौड़ पर सामाजिक नियंत्रण नहीं किया गया तो इसके परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं।

इस समय धर्म को भी धंधा बनाया जा रहा है। धर्म की आड़ में लोगों को पूंजीवादी व्यवस्था की ओर मोड़ा जा रहा है। यह भी सबसे खतरनाक स्थिति है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर यह संकल्प लेना होगा, आर्थिक समृद्धि के साथ मानवीय संवेदनाएं और पारिवारिक सुरक्षा प्राथमिकता बनें।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

इंडगो के बेड़े में दिसंबर 2027 तक 14 संकरे ए321 एक्सएलआर विमान शामिल होंगे

कम दूरी पर मुख्य फोकस, पर 2028 से ए350 से लंबी दूरी की तैयारी

नई दिल्ली ।

इंडिगो अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का जाल फैलाने की बड़ी तैयारी में है। इं डिगो के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने मंगलवार को बताया कि दिसंबर 2027 तक उसके बेड़े में कुल 14 संकरे ए321 एक्सएलआर विमान शामिल होने की उम्मीद है, जो लंबी दूरी तय कर सकते हैं। उन्होंने एविएशन इंडिया एंड साउथ एशिया 2026 में यह भी खुलासा किया कि कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 600 विमानों का बेड़ा तैयार करना है। अे धिकारी ने बताया कि फिलहाल ऐसे चार विमान बेड़े में हैं और इस साल एक और जोड़ा जाएगा। इन अधिक क्षमता वाले विमानों से विदेशों में नए गंतव्य जुड़ेंगे। उन्होंने दोहराया कि विमानन कंपनी का ध्यान कम दूरी की उड़ानों पर ही बना रहेगा। बोइंग 787 का परिचालन बंद कर चुकी इंडिगो को 2028 की दूसरी तिमाही से ए350-900 विमान मिलने शुरू होंगे। हालांकि, उन्होंने चेताया कि ए350 के उत्साह में कंपनी को अपनी कम दूरी की कुशल उड़ानों पर से ध्यान नहीं भटकना चाहिए। इंडिगो को उम्मीद है कि 2030 तक उसके बेड़े में 600 विमान होंगे (फिलहाल 440 से अधिक)। उन्होंने हवाई अड्डों से प्रभावी साझेदारी व निवेश पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही, साथ ही उनके ऊंचे शुल्क-करों की आलोचना भी की।

अब दुबई और सिंगापुर में यूपीआई से भुगतान संभव

बुर्ज खलीफा और यूनिवर्सल स्टूडियो जैसे प्रमुख स्थलों पर मिलेगी भुगतान की सुविधा

नई दिल्ली ।

भारतीय पर्यटक अब दुबई और सिंगापुर जैसे लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों में भारतीय पेमेंट मोड यूपीआई के जरिए आसानी से भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में इस नई सुविधा की जानकारी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेश यात्रा के दौरान भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट बुक करने और अन्य खरीददारी को आसान बनाना है। यह कदम भारतीयों को विदेश यात्रा के दौरान टिकट खरीदने के लिए विदेशी कार्ड या दूसरे अंतरराष्ट्रीय पेमेंट ऑप्शंस पर निर्भर रहने की झंझट से मुक्ति दिलाएगा। इससे न केवल उनकी यात्रा और अधिक सुविधाजनक होगी, बल्कि उन्हें करेंसी एक्सचेंज की जटिलताओं से भी नहीं जूझना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप दुबई घूमने जा रहे हैं और बुर्ज खलीफा का टिकट यूपीआई से बुक करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया बेहद सरल है। आपको बस बुर्ज खलीफा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, अपनी पसंद का टिकट पैकेज चुनना होगा और बुक नाओ पर क्लिक करके घूमने की तारीख व समय का चयन करना होगा। इसके बाद चेकआउट करते समय पेमेंट के विकल्प में यूपीआई को चुनकर आप आसानी से भुगतान कर सकते हैं। यह नई पहल विदेश जाने वाले भारतीयों को काफी सहूलियत प्रदान करेगी और वैश्विक स्तर पर भारतीय डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल को भी बढ़ावा देगी। यह भारतीय डिजिटल इकोसिस्टम के वैश्विक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आंध्र प्रदेश को मिली 1614 करोड़ की दक्षिण कोरियाई निवेश लॉटरी, तमिलनाडु चूका

हुंडई-किया के पुर्जे बनाने वाली तीन कंपनियां अनंतपुर में लगाएंगी फैक्ट्रियां

नई दिल्ली ।

भारत में निवेश के लिए राज्यों के बीच चल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा में आंध्र प्रदेश ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दक्षिण कोरिया की तीन प्रमुख ऑटो-पार्ट्स कंपनियों ने तमिलनाडु को पछाड़कर आंध्र प्रदेश में 1,614 करोड़ रुपये का निवेश करने का फैसला किया है। ये कंपनियां दुनिया की दिग्गज कार निर्माता हुंडई और किया को गाड़ियों के पुर्जे सप्लाई करती हैं। इस निवेश के तहत राज्य के अनंतपुर जिले में नई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी। इसमें ह्वासन 850 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, सियोयोन 514 करोड़ रुपये लगाएगी, और इवामेट 250 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कुल मिलाकर, यह ₹1,614 करोड़ का निवेश 1,418 संभावित रोजगार सृजित करेगा। तमिलनाडु, जो ऑटोमोबाइल कंपनियों का एक बड़ा केंद्र है और वहां हुंडई के प्लांट भी मौजूद हैं, इन कंपनियों को अपने यहां निवेश के लिए लुभा रहा था।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 1200 , निफ्टी 370 अंक उछला

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भी तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी हावी रहने से आया है। इसी कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सूचकांक भारी बढ़त के साथ बंद हुए, जिससे बाजार में उत्साह का माहौल है। इस तेजी का कारण हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज शेयरों में आया उछाल है। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1225.07 अंक बढ़कर 76,917.85 के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। इसी तरह, 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 370.05 अंकों की तेजी के साथ ही 23,810.85 के स्तर पर पहुंचा। गत दिवस भी बाजार में करीब 1.5 फीसदी की तेजी रही जिससे यह लगातार दूसरा ऐसा दिन रहा जब निवेशकों की पूंजी बढ़ी है।

आज अधिकर शेयरों में तेजी रही। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयर लाभ के साथ ही बढ़त पर बंद हुए, जबकि शेष 5 कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही। वहीं, निफ्टी में भी यही रुझान रहा। इसमें 50 में से 39 कंपनियों के शेयरों में बढ़त रहीजबकि 10 शेयरों में गिरावट आई और एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ।

दिग्गज शेयरों में हिंदुस्तान



यूनिलीवर के शेयरों ने लंबी छलांग लगाई और यह 4.16 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा, भारती एयरटेल , एचडीएफसी बैंक , एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में भी तेजी रही। आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी , टाइटन, एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी के शेयर भी उछले। । बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और सन फार्मा जैसे अन्य प्रमुख शेयरों में भी बढ़त रही। इस तेजी के बावजूद कुछ शेयर ऐसे भी रहे, जिन्हें नुकसान उठाना पड़ा। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी पावर ग्रिड के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरे। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक और एनटीपीसी 0.87 और ट्रेंट के शेयर भी गिरे। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजारों की बढ़त के साथ शुरुआत हुई।

रुपया बढ़त के साथ बंद

मुंबई ।



अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मंगलवार को 13 पैसे की बढ़त के साथ ही 94.71 पर बंद हुआ। इससे पहले आज सुबह बाजार 12 पैसे मजबूत होकर 94.72 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और घरेलू शेयर बाजार में विदेशी पूंजी के प्रवाह से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि हालांकि, अमेरिका में महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनाव से पहले डॉलर के मजबूत होने से दुनियाभर के निवेशकों के सतर्क रहने से रुपये की बढ़त सीमित रही। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.68 प्रति डॉलर पर खुला और फिर मजबूत होकर 94.60 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। इसके बाद यह डॉलर के मुकाबले 94.72 पर कारोबार करने लगा जो पिछले बंद भाव से 12 पैसे की बढ़त दिखाता है। वहीं रुपया सोमवार को आठ पैसे टूटकर 94.84 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.03 फीसदी बढ़कर 101.65 पर आ गया।

भारत में सोने की मांग 29 फीसदी घटी, मूल्य में 3 फीसदी की वृद्धि

आयात शुल्क, ऊंची कीमतें और पीएम की अपील बनी वजह

मुंबई ।

विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) के अनुसार भारत में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान सोने की मांग सालाना आधार पर 29 प्रतिशत घटकर 162.5 टन रह गई। आयात शुल्क में बढ़ोतरी, कीमतों में तेज उछाल और प्रधानमंत्री की खरीदारी कम करने की अपील इसके प्रमुख कारण रहे। हालांकि, इस अवधि में सोने की कुल मांग का मूल्य 3 प्रतिशत बढ़कर 2,41,900 करोड़ रुपये हो गया, जो उपभोक्ताओं की सोने के प्रति निरंतर प्राथमिकता को दर्शाता है। डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की इसी तिमाही में सोने की मांग 229.8 टन थी, जबकि समीक्षाधीन तिमाही में औसत भाव करीब 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। कुल आभूषण मांग 20 फीसदी घटकर 99.9 टन पर आ गई, पर मूल्य के लिहाज से यह 16 फीसदी बढ़कर 1,48,700 करोड़ रुपये दर्ज की गई। डब्ल्यूजीसी के एक अे धिकारी ने कहा कि उपभोक्ता अब हल्के वजन के आभूषणों और पुराने सोने के बदले नए आभूषण लेने जैसी रणनीतियों को अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि तीसरी तिमाही के अंत में कीमतों में आई गिरावट और आगामी त्योहारों व शादी के मौसम से मांग को समर्थन मिलने की उम्मीद है। डब्ल्यूजीसी ने पूरे साल के लिए भारत में सोने की मांग 625 से 675 टन रहने का अनुमान लगाया है।

डेरियस खंबाटा ने टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टी के तौर पर दोबारा नियुक्ति से किया इनकार

विदाई पत्र में टाटा संस की 17 सितंबर की बोर्ड बैठक को 'कलंक का दिन' बताया

नई दिल्ली।

टाटा संस में 66 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े शेयरधारक टाटा ट्रस्ट्स में नेतृत्व को लेकर विवाद गहरा गया है। वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर दोबारा नियुक्ति से इनकार कर दिया है। उनका कार्यकाल इसी माह खत्म हो जाएगा। अपने विदाई पत्र में, खंबाटा ने टाटा संस की 17 सितंबर की बोर्ड बैठक को 'कलंक का दिन' बताया, जिससे इस बड़े समूह के अंदर चल रही सत्ता और नियंत्रण की खींचतान एक बार फिर उजागर हो गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खंबाटा के जाने के बाद, एसडीटीटी में पांच ट्रस्टी होंगे। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा एसडीटीटी में एक 'स्थायी ट्रस्टी' हैं। इस मुद्दे पर कुछ ट्रस्टियों ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के सामने आपत्ति जताई है। अन्य मौजूदा ट्रस्टियों में वाइस-चेयरमैन विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन के साथ-साथ भास्कर भट और नेविल टाटा शामिल हैं। जहां पहले टाटा ट्रस्ट्स में ट्रस्टियों का नवीनीकरण एक सामान्य प्रक्रिया थी, वहीं पिछले दो सालों में आम सहमति न बन पाने पर वोटिंग करनी पड़ी है, जिससे विवाद पैदा हुए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक अपने विदाई पत्र में खंबाटा ने 28 जुलाई, 2025 को ट्रस्टों द्वारा लिए गए प्रस्तावों के समर्थन में अपने अडिग रुख का जिक्र किया। इन प्रस्तावों में आरबीआई के साथ बातचीत करके टाटा संस की लिस्टिंग का विरोध करना और शापूरजी पलोनजी समूह को उनकी मांगी गई नकद राशि उपलब्ध कराना शामिल था। इसके साथ ही एन चंद्रशेखरन को टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर तीसरे कार्यकाल के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। खंबाटा ने लिखा- अगस्त और सितंबर 2026 की हैरान कर देने वाली घटनाओं ने पिछली बातों को पीछे छोड़ दिया है। अगस्त 2026 में चंद्रशेखरन ने टाटा संस बोर्ड को लिखा था कि वे तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा नियुक्ति नहीं चाहेंगे, लेकिन इसके एक महीने बाद, टाटा संस बोर्ड की एक बैठक में चंद्रशेखरन को तीसरा कार्यकाल देने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसका नोएल टाटा ने विरोध किया। जुलाई 2025 का वह प्रस्ताव, जिसका जिक्र खंबाटा ने अपने पत्र में किया है, एसडीटीटी और एसआरटीटी दोनों की सर्वसम्मति से पास किया गया था। खंबाटा ने ही 28 मई, 2025 की बैठक में टाटा संस की संभावित लिस्टिंग के खिलाफ चेतावनी दी थी और इसे ट्रस्टों के अस्तित्व के लिए खतरा बताया था। उन्होंने लिखा यहां पूरा 'टाटा मॉडल' ही दांव पर लगा था।

मुकेश अंबानी ने रचा कीर्तिमान, एक दिन में 6.3 अरब डॉलर कमाए

रिलायंस के दमदार तिमाही नतीजों और शेयर में जोरदार उछाल से संपत्ति बढ़ी

मुंबई । रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने एक ही दिन में 6.3 अरब डॉलर (लगभग 55,000 करोड़ रुपये से अधिक) की संपत्ति अर्जित कर दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अरबपति का गौरव हासिल किया है। यह बढ़ोतरी उनकी प्रमुख कंपनी के बेहतर तिमाही नतीजों के बाद शेयर में आई जोरदार तेजी का परिणाम है। फोर्ब्स की रियल-टाइम अरबपतियों की ताजा सूची के अनुसार मुकेश अंबानी अब 88.8 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के 23वें सबसे अमीर व्यक्ति और भारत के सबसे धनी शख्स बन गए हैं। इस सूची में गौतम अदाणी 79.12 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 26वें स्थान पर हैं। संपत्ति में इस वृद्धि के मामले में वैश्विक स्तर पर स्पेन के अमानसियो ओर्टेगा (1.7 अरब डॉलर) और चीन के झोंग शांशान (1.5 अरब डॉलर) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 11.64 प्रतिशत चढ़कर 1,299 रुपये पर बंद हुआ, जो छह साल से अधिक समय में इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। यह उछाल कंपनी के सितंबर तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आया, जिसमें एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 33.8 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 29,550 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। कंपनी के तेल से रसायन और दूरसंचार व्यवसायों में मजबूत प्रदर्शन ने इस वृद्धि में अहम भूमिका निभाई। कंपनी के तेल से रसायन (ओ2सी) कारोबार में मजबूत प्रदर्शन और दूरसंचार व्यवसाय में वृद्धि ने खुदरा कारोबार की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति की भरपाई कर दी।

एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक का शेयर आठ फीसदी बढ़त के साथ सूचीबद्ध

नई दिल्ली ।



अपशिष्ट जल शोधन समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर अपने 330 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले करीब आठ प्रतिशत की बढ़त के साथ मंगलवार को बाजार में सूचीबद्ध हुआ। बीएसई पर शेयर ने निर्गम मूल्य से 7.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 354.05 रुपये पर कारोबार शुरू किया। एनएसई में यह 7.60 प्रतिशत की बढ़त के साथ 355.10 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 4,161.69 करोड़ रुपये रहा। एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को पिछले सप्ताह गुरुवार को बोली के अंतिम दिन 9.47 गुना अभिदान मिला था। कंपनी के 668 करोड़ रुपये के आईपीओ का मूल्य दायरा 313 से 330 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी की योजना नए शेयर जारी कर जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए करने की है।

एसीएमई सोलर की बीकानेर में 66.68 मेगावाट नई सौर ऊर्जा इकाई शुरू

हाइब्रिड परियोजना की परिचालन क्षमता 200 मेगावाट पार

नई दिल्ली ।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एसीएमई सोलर होल्डिंग्स ने राजस्थान के बीकानेर जिले में अपनी सौर ऊर्जा क्षमता का विस्तार किया है।

कंपनी की अनुषंगी एसीएमई रिन्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 66.68 मेगावाट की अतिरिक्त सौर ऊर्जा इकाई का सफलतापूर्वक परिचालन शुरू किया है।

इस नई क्षमता के साथ हाइब्रिड परियोजना की कुल परिचालन क्षमता बढ़कर 200.04 मेगावाट हो गई है। इसके परिणामस्वरूप एसीएमई सोलर की कुल परिचालन क्षमता अब करीब 3,190 मेगावाट हो गई है। यह परियोजना बीकानेर के केलां गांव में स्थित है और इसके लिए एनटीपीसी लिमिटेड के साथ 3.36 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा की दर से बिजली खरीद समझौता (पीपीए) किया गया है।

नई शुरू की गई क्षमता की वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) 4 नवंबर, 2026 निर्धारित है।

कंपनी को उम्मीद है कि वह वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही तक परियोजना की पूरी 300 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को चरणबद्ध तरीके से परिचालन में ले आएगी।

भारत में मीठी ड्रिंक्स से दूरी बना रहे लोग,जीरो शुगर की मांग दोगुनी

पेप्सी-कोक जैसी कंपनियां अपना रहीं नई रणनीति

नई दिल्ली ।

भारत का 60 हजार करोड़ रुपए का सॉफ्ट ड्रिंक बाजार एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। उपभोक्ता अब मीठे पेय पदार्थों के बजाय जीरो और लो शुगर ड्रिंक्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिससे पेप्सीको और कोका-कोला जैसी बड़ी कंपनियों को फायदा हो रहा है।

पेप्सीको के कुल वॉल्यूम में जीरो और लो शुगर ड्रिंक्स की हिस्सेदारी जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही में बढ़कर 88 फीसदी हो गई, जो पिछले साल 44 फीसदी थी।

कोका-कोला की डाइट और लाइट ड्रिंक्स की बिक्री में भी तेज उछाल आया है, जहां डाइट कोक की बिक्री में 150 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है और इनकी कुल हिस्सेदारी 60 फीसदी के पार पहुंच गई है।

इस बदलाव के पीछे उपभोक्ताओं में बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता के साथ-साथ चीनी की बढ़ती कीमतें भी एक बड़ा कारण हैं। पिछले साल 40-50 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अब 58-65 रुपए किलो तक पहुंच गई है।

पेप्सी की बॉटलिंग पार्टनर वरुण बेवरेजेज जैसी कंपनियों को जीरो शुगर उत्पादों से महंगी चीनी लागत के दबाव को कम करने में मदद मिली है।

वैश्विक संघर्षों की आंच में झुलसा करेली गुड़,दाम 4100 रुपए के पार

समुद्री मार्ग बाधित होने से कच्चे माल की किल्लत, निर्यात पर भी खतरा

भोपाल ।

पश्चिम एशिया और रूस-यूक्रेन में जारी संघर्ष का सीधा असर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के प्रसिद्ध करेली गुड़ पर दिखाई दे रहा है। इन युद्धों के चलते उर्वरकों की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे गन्ने की खेती की लागत बढ़ गई है और गुड़ के दाम पिछले साल के मुकाबले 10-15 प्रतिशत बढ़कर 4,100 रुपये प्रति क्विंटल के पार पहुंच गए हैं। पिछले साल इसी समय करेली मंडी में गुड़ का भाव 3,500 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा था। यह बढ़ोतरी किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई है। किसानों का कहना है कि गन्ने की खेती में प्रति एकड़ 60,000 रुपये का खर्च आता है, जिसमें मजदूरी, सिंचाई और खासकर उर्वरकों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। गुड़ कारोबारी भी मानते हैं कि उर्वरक कीमतों में तेज वृद्धि ने इस साल गुड़ को महंगा कर दिया है। होर्मुज स्ट्रेट, लाल सागर और काला सागर जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के बंद होने से सल्फर और रॉक फॉस्फेट जैसे उर्वरक बनाने वाले कच्चे माल की किल्लत पैदा हो गई है। खेतान केमिकल्स के ब्रांड मैनेजर मयंक जोशी के अनुसार, युद्ध से पहले 6,000-10,000 रुपये प्रति टन मिलने वाला सल्फर अब 1 लाख रुपये प्रति टन हो गया है, जबकि रॉक फॉस्फेट भी तीन गुना महंगा होकर 14,000-15,000 से 30,000-35,000 रुपये प्रति टन पर पहुंच गया है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से उर्वरक कंपनियों ने उत्पादन घटा दिया है, जिससे बाजार में कीमतें और बढ़ गई हैं। स्थानीय किसान प्रवासी मजदूरों पर निर्भर हैं, जिनकी मजदूरी भी बढ़ी है। एक एकड़ खेत में बोआई का मेहनताना ही करीब 6,000 रुपये देना पड़ता है। मध्य प्रदेश का लगभग 75 फीसदी गन्ना नरसिंहपुर में ही बोया जाता है, जहां 2,000 से अधिक गुड़ उत्पादन इकाइयां हैं। हालांकि, राज्य में कोई घोषित गन्ना नीति नहीं होने से किसानों को अपनी उपज की कीमत के लिए मिल मालिकों पर निर्भर रहना पड़ता है। जीआई टैग प्राप्त करेली गुड़ का बड़ी मात्रा में खाड़ी देशों और मॉरीशस जैसे देशों में निर्यात होता है, लेकिन उत्पादन लागत में वृद्धि अब इसके निर्यात पर भी प्रतिकूल असर डाल सकती है।

ईरान पर अमेरिकी हमले से कच्चे तेल में फिर उबाल

ब्रेंट क्रूड 105 डॉलर के पार, अमेरिका ने हमले को बताया बचाव का कदम

नई दिल्ली ।

अमेरिका द्वारा ईरान के केश्म द्वीप पर किए गए हमले की खबर से मंगलवार को शुरुआती एशियाई कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला। इस घटना ने पश्चिम एशिया में पिछले आठ महीने से जारी संघर्ष के और गहराने की आशंका पैदा कर दी है, जिससे क्षेत्र से वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति लंबे समय तक प्रभावित रहने की चिंता बढ़ गई है। यह उछाल सोमवार को ब्रेंट क्रूड में आई 7.63 फीसदी की बड़ी गिरावट के बाद आया है, जो 104.77 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.5 फीसदी बढ़कर 105.25 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड भी 0.5 फीसदी की तेजी के साथ 96.93 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर हमला किया है। कुछ अधिकारियों के मुताबिक, ये हमले बचाव के मकसद से किए गए थे, ताकि ईरान को होर्मुज स्ट्रेट में कारोबारी जहाजों पर हमला करने से रोका जा सके। केसीएम ट्रेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वाटरर ने कहा कि इस खबर से कच्चे तेल की कीमतों में युद्ध से जुड़ा जोखिम फिर बढ़ गया है। वैश्विक आपूर्ति और राजनीतिक दबाव होर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ है, क्योंकि संघर्ष शुरू होने से पहले दुनिया के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कुल आपूर्ति का करीब पांचवां हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता था। पश्चिम एशिया में किसी भी नई सैन्य कार्रवाई की खबर का असर कच्चे तेल की कीमतों पर तुरंत दिखाई देता है। अमेरिका में मंगलवार को मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं और ईरान युद्ध के कारण पेट्रोल की ऊंची कीमतें राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर संघर्ष खत्म करने का दबाव बढ़ा रही हैं, ऐसे में यह हमला राजनीतिक रूप से भी अहम है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1



बच्चों को घर बैठे खेल-खेल में सिखाएं गणित के गुण

कोरोना महामारी के दौरान बच्चे अपने पाठ्यक्रम में से ऐसी विभिन्न कक्षाओं में दाखिला और भाग ले रहे हैं जो उनके कौशल को बढ़ाने के लिए उनके स्कूल द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह पैटर्न विभिन्न आयु समूहों में देखा गया है जिसके कारण भारत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की मांग बढ़ रही है।

कोरोना वायरस महामारी के बाद कई छात्र काफी मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं। इस तनाव को दूर करने के लिए कई छात्र नए-नए हुनर सीख रहे हैं। ऐसे में भारत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की मांग काफी बढ़ गई है। माता-पिता अपने बच्चों को नए कौशल सिखाने के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को गणित और सांख्यिकी गणना सिखाना चाहते हैं तो अबेकस ट्रेनिंग क्लास की मदद से आप अपने बच्चों को खेल में गणित पढ़ा सकते हैं।

कोरोना महामारी के दौरान बच्चे अपने पाठ्यक्रम में से ऐसी विभिन्न कक्षाओं में दाखिला और भाग ले रहे हैं जो उनके कौशल को बढ़ाने के लिए उनके स्कूल द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह पैटर्न विभिन्न आयु समूहों में देखा गया है जिसके कारण भारत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की मांग बढ़ रही है। माता-पिता अलग-अलग ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जिसके माध्यम से उनके बच्चों को रचनात्मक सीखने के माहौल में पाला जा सकता है। गणित और संख्या कुछ बच्चों के लिए स्वाभाविक रूप से आती है, लेकिन जब गणना की बात आती है तो स्कूल और कॉलेज के छात्रों का एक बड़ा हिस्सा कुछ हद तक संघर्ष करता है। अबेकस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सदियों से मौजूद है और इसे अंकगणितीय कौशल और संख्यात्मक प्रवाह को विकसित करने के लिए दुनिया भर में सबसे अच्छे उपकरणों में से एक माना जाता है।

अबेकस टूल का उपयोग गणितीय कार्यों जैसे जोड़, घटाव, गुणा, वर्ग या घनमूल को करने के लिए किया जाता है। अबेकस का उपयोग दशमलव अंक, ऋणात्मक संख्या और बहुत कुछ गिनने के लिए भी किया जा सकता है। अपने गणना कौशल में सुधार के अलावा, अबेकस सीखने से बच्चे के समग्र विकास में मदद मिल सकती है। अबेकस सीखने के कुछ लाभ इस प्रकार हैं :

- कैलकुलेशन की गति और सटीकता में सुधार करता है
- विश्लेषणात्मक कौशल और तार्किक रीजनिंग का निर्माण करता है
- गणित में रुचि पैदा करता है
- एकाग्रता और अवलोकन शक्ति को बढ़ाता है
- मेमोरी में सुधार करता है
- आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान बनाता है



यहां भारत में पांच ऐसे प्लेटफार्मों के बारे में बताया गया है जो 100 प्रतिशत डिजिटल एबेकस प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और युवाओं को भविष्य के रोल मॉडल बनने के लिए प्रेरित करते हैं।

ब्रिटिश यूथ इंटरनेशनल कॉलेज

यूके स्थित प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन अबेकस शिक्षण मंच लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। उनके मंच में पूरी तरह कार्यात्मक वर्चुअल अबेकस है जो बच्चों के समग्र मानसिक विकास के लिए इंटरैक्टिव प्रशिक्षक के नेतृत्व वाली अबेकस शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है। ये ऑनलाइन कक्षाएं चरण-दर-चरण अप्रोच प्रदान करती हैं जिसका उद्देश्य छात्रों को अबेकस को ध्यान में रखकर मार्गदर्शन करना और कैलकुलेटर की तुलना में तेजी से संख्या की गणना करना है। शिक्षक प्रत्येक छात्र को गहन शिक्षण प्रदान करते हैं। वे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव जोड़, दशमलव घटाव, दशमलव गुणा और दशमलव भाग को कवर करते हैं। वे एकमात्र अबेकस कंपनी हैं जो दशमलव आधारित गणना प्रदान करती हैं।

उडेमी

उदमी अबेकस कोर्स का उद्देश्य आपकी गणना, क्षमता, संख्या बोध और मानसिक अंकगणित को बेहतर बनाने में मदद करके मस्तिष्क का विकास करना है। यह पाठ्यक्रम मल्टीमीडिया और एनिमेशन के जरिये आपको सिखाएगा कि अबेकस पर सही और तेज बुनियादी गणित संचालन कैसे करें। इन अबेकस ऑनलाइन कक्षाओं को शुरू करके बच्चे अबेकस पर संख्याएं रखने, हल करने और जोड़ और घटाव को समझने में सक्षम होंगे।

अबेकस सुपरमैथ्स

'सुपरमैथ्स' छात्रों को अबेकस टूल का उपयोग करने के लिए एक दोस्ताना और इंटरैक्टिव मंच प्रदान करता है। उनकी कक्षाएं आपको ऑनलाइन वर्कशीट पर काम करके मानसिक सिद्धांत अवधारणाओं को अभ्यास में लाने की अनुमति देती हैं। यह कोर्स दो ट्रैक में आता है, जूनियर और सीनियर। पहले ट्रैक में 11 स्तर होते हैं जबकि दूसरे वरिष्ठ ट्रैक में 8 स्तर होते हैं। प्रत्येक स्तर के अंत में एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाती है जिसके बाद छात्र को अगले स्तर पर पदोन्नत किया जाता है। वे प्रशिक्षक के नेतृत्व में आवेदन आधारित वीडियो कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाते हैं।

अबेकस मास्टर

अबेकस मास्टर ने अबेकस को अधिक रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए अनूठी विशेषताओं के साथ एक व्यापक शिक्षण मंच बनाया है। यह ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म 5-12 वर्ष की आयु के बीच के छात्रों को अबेकस प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें आठ स्तर शामिल होते हैं जो बुनियादी से लेकर उन्नत अबेकस गणनाओं तक सभी विषयों को कवर करते हैं। छात्र इस पाठ्यक्रम को अपनी गति के हिसाब से ले सकते हैं; हालाँकि, पोर्टल पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए प्रत्येक स्तर पर कम से कम दो महीने बिताने का सुझाव देता है। उनकी कक्षाएं एनिमेशन, अंजान वीडियो और प्रैक्टिस वर्कशीट की मदद से दी जाती हैं।

स्मार्ट किड अबेकस

स्मार्ट किड की 'अबेकस फ्रेंचाइजी' बच्चों के लिए अबेकस ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करती है। ये कक्षाएं सप्ताह में एक बार 45 मिनट के लिए आयोजित की जाती हैं। समय में कोई पाबन्दी नहीं है और छात्र कई प्रकार के पाठ्यक्रमों में से चुन सकते हैं। यह आठ स्तरीय पाठ्यक्रम है जिसमें 5 बुनियादी और 3 अग्रिम स्तर हैं। पाठ्यक्रम 4-14 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों के लिए डिजाइन किए गए हैं और ये पाठ्यक्रम कौशल के विकास के साथ-साथ संपूर्ण मस्तिष्क विकास को बढ़ावा देते हैं।



फ्लाइट में यात्रियों की मेहमान नवाजी कर कमाएं हजारों

केबिन क्रू की जिम्मेदारी फ्लाइट में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना और यात्रियों को फ्लाइट के नियम समझाना होता है। बहुत से लोग केबिन क्रू बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि केबिन क्रू कैसे बनें।

केबिन क्रू का मतलब होता है केबिन के कर्मचारी। किसी भी फ्लाइट में जहाँ यात्री बैठते हैं, उसे केबिन कहते हैं। फ्लाइट में यात्रियों की सेवा और सुरक्षा के लिए जो टीम होती है, उसे केबिन क्रू कहते हैं। केबिन क्रू की जिम्मेदारी फ्लाइट में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना और यात्रियों को फ्लाइट के नियम समझाना होता है। बहुत से लोग केबिन क्रू बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि केबिन क्रू कैसे बनें। आज के इस लेख में हम आपको केबिन क्रू बनने के लिए जरूरी योग्यता, प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देंगे

योग्यता

- उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम में पास होना चाहिए। या किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक की हो तो आप केबिन क्रू की जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक की ऊंचाई 157 से 170 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 17 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

जरूरी कौशल

- केबिन क्रू बनने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए।
- केबिन क्रू बनने के लिए दूसरों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने का ढंग होना चाहिए।
- आपके शरीर पर किसी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए।
- आपकी अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
- केबिन क्रू बनने के लिए अच्छी पर्सनालिटी और गुड लुक्स भी जरुरी होते हैं।

कोर्सेज

- डिप्लोमा इन केबिन क्रू एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट
- डिप्लोमा इन एयरलाइन एंड ट्रेवल मैनेजमेंट
- डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट
- डिप्लोमा इन एयरलाइन केबिन क्रू
- सर्टिफिकेट कोर्स इन एयर हॉस्टेस

केबिन क्रू कैसे बनें

- एयरलाइन कंपनियां समय-समय पर केबिन क्रू की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करती हैं।
- केबिन क्रू का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आवेदक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
- इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आवेदक की शारीरिक जाँच और मेडिकल टेस्ट होता है।
- मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है।
- इन सभी टेस्ट्स को पास करने वाले उम्मीदवारों का चयन केबिन क्रू के लिए होता है।

सैलरी

शुरुआत में बतौर केबिन क्रू आपकी सैलरी प्रतिमाह 30,000 रूपये से 50,000 रूपये तक हो सकती है। हालंकि, समय के साथ अनुभव होने पर सैलरी बढ़कर 70 हजार रूपये से 1 लाख रूपये प्रतिमाह तक हो सकती है।



वैकल्पिक चिकित्सा में कॅरियर बनाना चाहते हैं तो चुनें मैग्नेटिक थेरेपी

एक मैग्नेटो चिकित्सक को मैग्नेटोमीटर के सही उपयोग के बारे में पता होना चाहिए, जो एक चुंबक के ध्रुवों को निर्धारित करता है। इसके अलावा आपको चुंबकीय चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों की भी सही जानकारी होनी चाहिए।

मैग्नेटिक थेरेपी, जिसे मैग्नेट थेरेपी या मैग्नो थेरेपी भी कहा जाता है, वास्तव में एक वैकल्पिक चिकित्सा उपचार है, जिसमें विभिन्न रोगों के उपचार के लिए चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बेहद सिंपल, इफेक्टिव, सुरक्षित व पूरी तरह से दर्दरहित प्राकृतिक उपचार है। चुंबकीय चिकित्सा को एक विज्ञान के साथ-साथ एक कला के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के विभिन्न अंगो, रोगों को जानने के साथ-साथ व मैग्नेट के उचित उपयोग को जानना भी उतना ही जरूरी है। विज्ञान में, चुंबकीय चिकित्सा एक्यूपंक्चर के समान है। वहीं कला में, इसमें विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों पर विभिन्न आकारों और शक्तियों के मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बेहद डिफरेंट चिकित्सा थेरेपी है। तो चलिए जानते हैं कि इस क्षेत्र में कैसे बनाएं कॅरियर-

स्किल्स

एक मैग्नेटो चिकित्सक को मैग्नेटोमीटर के सही उपयोग के बारे में पता होना चाहिए, जो एक चुंबक के ध्रुवों को निर्धारित करता है। इसके अलावा आपको चुंबकीय चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों की भी सही जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें मानव शरीर व उसके महत्वपूर्ण अंगों की रचना व उसके विज्ञान के बारे में भी पता होना चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता

भारत में केवल कुछ ही संस्थान मैग्नेट थैरेपी पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं। मैग्नेट थेरेपी में सर्टिफकिट, डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 10, 2 है और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक होना आवश्यक है। डिप्लोमा कोर्स की अवधि 1 वर्ष की है और स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स 2 वर्ष का है। कुछ संस्थान शार्ट टर्म डिप्लोमा और मास्टर डिप्लोमा कोर्स भी करवाते हैं, जिनकी अवधि एक से तीन महीने की होती है। एक मैग्नेटिक थेरेपिस्ट प्राइवेट व पब्लिक हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल या वैकल्पिक उपचार चिकित्सा केन्द्रों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक थेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वह उपचार के लिए मैग्नेटिक ज्वैलरी, ब्रेसलेट व अन्य उत्पादों को भी बेच सकते हैं। एक मैग्नेटिक थेरेपिस्ट की आय असीमित है। उनकी आय उनके चिकित्सीय कौशल पर निर्भर करती है। सेल्फ इंपलायड मैग्नेटिक थेरेपिस्ट घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। उनका एक सेशन करीबन 20 से 30 मिनट का होता है।

प्रमुख संस्थान

- इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता
- एक्यूप्रेशर रिसर्च, टेनिंग व टीटमेंट इंस्टीट्यूट, जोधपुर
- ऑल इंडिया पैरा मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड अल्टरनेटिव मेडिकल काउंसिल, लुधियाना
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे
- कॉलेज ऑफ क्लिनकिल मैग्नेटोलॉजी और प्राण हीलिंग कॉलेज, त्रिशूर
- इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, बैंगलोर
- महेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, जयपुर





एक्वापॉनिक्स फार्मिंग में है बेहतर भविष्य

क्वापोनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एक्वाकल्चर जिसमें मछली पालन होता है और दूसरा हाइड्रोपोनिक जिसमें पानी पर खेती होती है। एक्वापोनिक्स में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियाँ और पौधे एक साथ उगाए जा सकते हैं। इसमें परंपरागत खेती की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है।

आज के समय में एग्रीटेक स्टार्टअप बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। एक्वापोनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एक्वाकल्चर जिसमें मछली पालन होता है और दूसरा हाइड्रोपोनिक जिसमें पानी पर खेती होती है। एक्वापोनिक्स में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियाँ और पौधे एक साथ उगाए जा सकते हैं। इसमें परंपरागत खेती की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है जबकि इसमें पौधे दोगुनी रफ्तार से बढ़ते हैं। एक्वापॉनिक्स में एक फिश टैंक में मछली पालन किया जाता है और दूसरी तरफ पानी पर हाइड्रोपोनिक खेती का सिस्टम बनाया जाता है। फिश टैंक में मछलियां फीड खाने के बाद करीब 70 फीसदी तक मल निकालती हैं जिसमें अमोनिया होता है। इसके बाद फिश टैंक से अमोनिया वाले पानी को हाइड्रोपोनिक खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है तो वहां मौजूद बैक्टीरिया इसे नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं। यह पौधों के विकास के लिए बहुत ही अहम होता है। इसके बाद पानी को फिर से प्यूरिफाई किया जाता है और दोबारा मछलियों के टैंक में डाला जाता है। इस तरह एक ही पानी बार-बार इस्तेमाल होता रहता है और पानी की बचत होती है।

एक्वापोनिक फार्मिंग सेटअप तैयार करने में कितनी लागत आएगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बड़ा सेटअप तैयार करना चाहते हैं या छोटा। उदाहरण के लिए अगर आप एक एकड़ जमीन पर एक्वापोनिक फार्मिंग करते हैं तो आपका करीब 3 करोड़ रूपए तक का खर्चा आ सकता है। इसके साथ ही अगर आप मुनाफा चाहते हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी वाली चीजें इस्तेमाल करनी होंगी। एक्वापोनिक खेती से हुई पैदावार पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है इसलिए आप इसके लिए सामान्य की तुलना में दो से तीन गुना कीमत कमा सकते हैं। हालाँकि, आपको पैदावार से पहले ही उसे बेचने की तैयारी कर लेनी होगी वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप बड़े-बड़े रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट और फाइव स्टार होटलों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

ऑस्ट्रेलिया में सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत

मेलबर्न, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में सप्ताहांत के दौरान हुए सड़क हादसों में आठ लोगों की मौत हो गई। इनमें चार लोग मोटरसाइकिल चला रहे थे और तीन कार चला रहे थे। रविवार शाम मेलबर्न के ब्राइटन ईस्ट इलाके में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक और बाइक सवार दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार एक बच्चा मामूली रूप से घायल हुआ। इससे पहले शनिवार को राज्य के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में एक वाहन की टक्कर से 75 साल की महिला की मौत हो गई थी। वहीं, जिलॉन्ग के पास ई-बाइक और कार की टक्कर में दो किशोर घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई गई है।

नेपाल : बर्फबारी में फंसे छह भारतीय पर्यटकों का रेस्क्यू

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के शे-फोक्सुंडो नेशनल पार्क इलाके में भारी बर्फबारी के कारण फंसे छह भारतीय पर्यटकों को सोमवार सुबह सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें दो महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, सभी एक नवंबर से संपर्क से बाहर थे। पर्यटकों को निजी हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। फिलहाल सभी का डोल्पा जिले के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। ये पर्यटक शे-फोक्सुंडो झील घूमने गए थे। लौटते समय भारी बर्फबारी के कारण नुमला और वागला दर्रे में फंस गए। खराब मौसम के चलते रविवार को सेना का हेलीकॉप्टर भी उन्हें बचाने में नाकाम रहा था। प्रशासन ने पहले ही इलाके में भारी बर्फबारी को देखते हुए पर्यटकों को वहां न जाने की चेतावनी दी थी।

'बांग्लादेशी कपड़ा श्रमिकों का प्रदर्शन, कारखाने बंद

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में कपड़े बनाने वाले श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शनों के बाद सरकार ने वेतन की समीक्षा के लिए वेतन बोर्ड के गठन का एलान किया है। न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हो रहे इन प्रदर्शनों के चलते देश भर में 500 से अधिक कारखाने बंद करने पड़े हैं, और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। यह विवाद उस उद्योग के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है, जो लगभग 40 लाख श्रमिकों को रोजगार देता है। बांग्लादेश में 80% से अधिक निर्यात आय पैदा करता है और दुनिया के कई बड़े पश्चिमी ब्रांडों को कपड़े सप्लाई करता है।

4.2 करोड़ बच्चों को पछाड़ 11 साल की मयार ने जीता अरब रीडिंग चैलेंज

दुबई , एजेंसी। मिस्र की 11 साल की छात्रा मयार मोहम्मद ने दुबई में आयोजित 8वें 'अरब रीडिंग चैलेंज' में दुनिया भर के 4.02 करोड़ से अधिक छात्रों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। दुबई ओपेरा में आयोजित समारोह में यूएई के उपराष्ट्रपति, पीएम व दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने मयार को इस ऐतिहासिक जीत के लिए सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता को जीतने पर मयार को इनाम के रूप में 5 लाख दिरहम (लगभग 1.14 करोड़ रुपये) की राशि मिली है। मिस्र की एक प्राइमरी स्कूल की छात्रा मयार ने दुबई में फाइनल स्टेज तक पहुँचने और उसे जीतने के लिए अलग-अलग विषयों की दर्जनों किताबों को न केवल पढ़ा, बल्कि उनका गहराई से विश्लेषण भी किया। प्रतियोगिता इतनी कठिन थी कि दूसरे स्थान के लिए तीन छात्रों के बीच टाई हो गया।

ट्रंप ने किसानों को दिया 1.42 लाख करोड़ का पैकेज

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिकी कृषि उत्पादकों के लिए 15 अरब डॉलर(1.42 लाख करोड़ रुपये) की वित्तीय मदद और योजनाओं का वादा किया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को डीजल और उर्वरक की उन बढ़ी हुई लागतों से राहत दिलाना है, जिन्हें उन्हें मुख्य रूप से ट्रंप के टैरिफ और ईरान के साथ युद्ध के कारण भुगतना पड़ा है। ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए ट्रंप ने रविवार को आयोवा और कंसास का दौरा भी किया। कुल 15 अरब डॉलर में से आधे से अधिक यानी 8 अरब डॉलर किसानों को मिलने वाले एकमुश्त भुगतान के रूप में दिए जाएंगे।

फ्लोरिडा में विमान हादसा, रिहायशी इलाके के पास निजी जेट क्रैश; प्लेन में सवार सभी 9 लोगों की मौत

फ्लोरिडा, एजेंसी। अमेरिका के फ्लोरिडा में रविवार को एक बिजनेस जेट क्रैश हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 9 लोगों की मौत हो गई। एएफपी के मुताबिक, विमान टेक्सास से बहामास जा रहा था। हादसे से कुछ देर पहले पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कहा, 'विमान तेजी से नीचे गिर रहा है, हम जमीन से टकराने वाले है। अब वक्त नहीं बचा।' इसके कुछ ही देर बाद विमान सड़क के पास जमीन से टकरा गया। टक्कर होते ही जोरदार धमाका हुआ जमीन पर बड़ा गड्ढा बन गया और आसपास के इलाके में आग फैल गई। हादसे की जगह राष्ट्रपति ट्रम्प के मार-ए-लागो आवास से करीब 14 किलोमीटर दूर है।

क्रैश से पहले पायलट ने 'मेडे' कॉल दी थी : एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग सामने आई है। इसमें पायलट ने बताया कि मौसम खराब हो रहा है। विमान में बर्फ जम रही है और तेज झटके लग रहे हैं। हालात बिगड़ने पर पायलट ने 2 हजार फीट और ऊंचाई पर जाने की अनुमति मांगी। इसी दौरान विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। स्थिति बिगड़ती देख पायलट ने इमरजेंसी घोषित कर दी।

पायलट ने रेडियो पर कहा, हम 8 हजार फीट नीचे जा रहे हैं... मेडे, मेडे... हम 10 हजार फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिर रहे हैं। हम जमीन से टकराने वाले हैं

30 हजार फीट/मिनट की रफ्तार से नीचे गिरा विमान : विमान हादसे से पहले 35 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। नीचे गिरते समय विमान की अधिकतम रफ्तार 30 हजार फीट प्रति मिनट तक पहुंच गई। अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी ने बताया कि यह हादसा दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर हुआ। उन्होंने इसे बेहद दर्दनाक हादसा बताया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जांच में मदद के लिए अपनी टीम भेज रहा है। यह टीम नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के साथ मिलकर हादसे की जांच करेगी।



600 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया : हादसा रिहायशी इलाके में हुआ था। फ्लोरिडा के अधिकारियों के मुताबिक, विमान के मलबे और हादसे के असर के कारण करीब 600 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उनके लिए दो शेल्टर बनाए गए। एविएशन इंडस्ट्री की वेबसाइट एविएशन इंटरनेशनल न्यूज के मुताबिक, हादसे का शिकार विमान साल 2004 में बना था। यानी हादसे के समय यह करीब 22 साल पुराना था। इस दौरान इलाके में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ तूफान भी था। हालांकि, अभी यह साबित नहीं हुआ है कि खराब मौसम ही हादसे की वजह था। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि विमान क्रैश से पहले बिजली की लाइन से टकराया था। अधिकारियों ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है।

रिहायशी इलाके के पास सड़क पर गिरा विमान : हादसे का शिकार हुआ विमान लियरजेट-60 था। यह दक्षिण फ्लोरिडा के एक रिहायशी इलाके के ऊपर से गुजरते समय अचानक नीचे की ओर गिरा और सड़क के पास जोरदार धमाके के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद विमान में भीषण आग लग गई और आसमान में आग का बड़ा गोला दिखाई दिया। विमान सड़क के पास गिरा, जहां जमीन पर बड़ा गड्ढा बन गया। घटनास्थल पर चारों ओर आग की लपटें और काले धुएं का गुबार फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विमान रिहायशी मकानों के बेहद करीब गिरा। हादसे के दौरान वह घरों से कुछ ही दूरी पर सड़क के पास जा गिरा। मौके पर मौजूद लोग यह देखकर हैरान थे कि विमान मकानों और वहां से गुजर रहे वाहनों से टकराने से बाल-बाल बचा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हादसे में आसपास के मकानों को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं।

कारों में बैठे लोगों ने बनाया हादसे का वीडियो : हादसे के समय आसपास से गुजर रही कारों में बैठे कुछ लोगों ने विमान के आसमान से तेजी से नीचे गिरने का वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में विमान सड़क के पास गिरने के बाद आग के बड़े गोले में बदलता दिखाई दिया। घटनास्थल पर विमान के मलबे और सड़क के टूटे हिस्सों के आसपास आग की लपटें उठती रहीं।

हादसा मिलिट्री ट्रेल और 10वीं एवेन्यू नॉर्थ के पास हुआ। सूचना मिलते ही दमकलकर्मी और अन्य आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंच गईं। पाम बीच काउंटी शेरिफ कार्यालय ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़क के दोनों ओर यातायात बंद कर दिया और वाहन चालकों से उस इलाके में जाने से बचने की अपील की।

क्वाड का आर्थिक सुरक्षा पर जोर, महत्वपूर्ण खनिजों और एआई में सहयोग बढ़ाएंगे भारत समेत चारों देश

वाशिंगटन , एजेंसी। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक और सामरिक सहयोग को नई दिशा देने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), समुद्री सुरक्षा और डिजिटल संपर्क के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। चारों देशों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाले आर्थिक दबाव, मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और बाजार को विकृत करने वाली नीतियों पर चिंता जताई है। अमेरिका के अटलांटा में 31 अक्टूबर को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई।

इसके बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। जिसमें आर्थिक सुरक्षा को वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए जरूरी बताया गया। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी संयुक्त बयान के अनुसार, चारों देशों ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर प्रतिबद्धता दोहराते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया। उनका कहना है कि महत्वपूर्ण उद्योगों में जरूरत से ज्यादा उत्पादन, गैर-बाजार नीतियां और मनमाने निर्यात प्रतिबंध वैश्विक व्यापार तथा आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। क्वाड के महत्वपूर्ण खनिज पहल ढांचे के तहत चारों देश इलेक्ट्रॉनिक कचरे और कबाड़ से महत्वपूर्ण खनिजों को दोबारा हासिल करने, प्रसंस्करण संयंत्रों और रिफाइनरियों के विकास तथा वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम करेंगे। अमेरिका ने 'भारत और आसियान देशों में कचरे से महत्वपूर्ण खनिज निकालने वाली सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक करोड़ डॉलर की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है।' इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम करना है। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योगों में इन खनिजों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए यह सहयोग आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से अहम है। एआई के क्षेत्र में भी क्वाड ने बड़ी पहल की घोषणा की है। संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार, चारों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद एआई तकनीक तक पहुंच बढ़ाने के लिए आठ करोड़ 50 लाख डॉलर से अधिक की तकनीकी और वित्तीय सहायता देने का इरादा रखते हैं। इसके लिए क्वाड एसआई एक्सेलेरेटर के माध्यम से काम किया जाएगा। विज्ञप्ति में 'एसआई' यानी 'सुपर इंटेलिजेंस' का उल्लेख किया गया है, जिसे भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में परिभाषित किया गया है।

हूती के खिलाफ सऊदी गठबंधन का अभियान, दावा- अहम सैन्य संसाधनों को किया तबाह

रियाद , एजेंसी। यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा है कि उसने हूती गुट के महत्वपूर्ण संसाधनों को निष्क्रिय करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मल्की ने रविवार (स्थानीय समयानुसार) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, 'अभियान रविवार सुबह चलाया गया। यह कदम सऊदी अरब और यमन में नागरिकों और नागरिक ठिकानों पर हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों के जवाब में उठाया गया था।' अल-मल्की ने बताया कि हूती विद्रोही इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने युद्ध प्रयासों को समर्थन देने और अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कर रहे थे, खासकर अपने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों के लिए। समाचार एजेंसी 'सिन्हुआ' के अनुसार, उन्होंने इस अभियान की जगह या इसके नतीजों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। इसके अलावा, रविवार को यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन में स्थानीय निवासियों और एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि शहर में एक सरकारी सैन्य ठिकाने के पास हूती मिसाइल गिरी, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। अपना नाम न बताने की शर्त पर 'सिन्हुआ' से बात करते हुए अधिकारी ने बताया कि मिसाइल पश्चिमी अदन के अल-बुरैका जिले में उस सैन्य ठिकाने के पास गिरी, जिसका इस्तेमाल सऊदी समर्थित यमनी सरकारी सेना कर रही थी। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज कई इलाकों तक सुनाई दी। हूती समूह ने इस हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। अदन, जो यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का अस्थायी मुख्यालय है, हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों द्वारा किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में आ गया है। यमन 2014 के आखिर से ही संघर्ष में उलझा हुआ है। उस समय हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था।

'नियमों का उल्लंघन' करने वाले तेल टैंकरों में विस्फोट, बारूदी सुरंग से टकराए थे दोनों: ईरान

तेहरान , एजेंसी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की नौसेना ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पिछले कुछ घंटों के दौरान दो 'नियम उल्लंघन करने वाले' सुपरटैंकर समेत एक तेल टैंकर में धमाका हुआ। कथित तौर पर ये दोनों बारूदी सुरंगों (नेवल माइन्स) से टकराए जिससे विस्फोट हुआ और दोनों वहीं रुक गए। रविवार (स्थानीय समय) को आईआरजीसी के आधिकारिक समाचार आउटलेट 'सिपाह न्यूज' पर जारी एक बयान में, नौसेना ने कहा कि ये टैंकर जलडमरूमध्य में एक 'अनधिकृत' (बिना अनुमति वाले) रास्ते से गुजर रहे थे। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, इसमें आगे कहा गया कि सुपरटैंकर में 'एक जोरदार विस्फोट हुआ और वह धू-धू कर जल रहा है।' बताया गया कि दोनों



जहाजों ने अपने नेविगेशन और पहचान प्रणालियों को बंद कर रखा था। ईरान ने 28 फरवरी को इस स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। उसने इजरायल और अमेरिका के जहाजों-या उनसे जुड़े जहाजों - के सुरक्षित आवागमन पर रोक लगा दी थी। यह कदम ईरानी क्षेत्र पर उनके संयुक्त हमलों के बाद उठाया गया था। इससे पहले, आईआरजीसी के प्रवक्ता होसैन मोहेब्बी ने कहा कि ईरानी बलों ने 'दुश्मन' को नुकसान पहुंचाने और रोकने के लिए एक विशाल युद्धक्षेत्र तय कर लिया है। अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी के हवाले से सिन्हुआ ने बताया कि रविवार (स्थानीय समय) को ईरान के दक्षिण-पूर्वी केरमान प्रांत में एक सम्मेलन में मोहेब्बी ने कहा कि ईरानी बल 'दुश्मन को निर्णायक जवाब देने के लिए' पहले से कहीं अधिक तत्पर हैं। उन्होंने सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई द्वारा वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को दिए गए हालिया आदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम लीडर के इन निर्देशों ने 'युद्ध का एक नया अध्याय' शुरू कर दिया है। मोहेब्बी ने खामेनेई की उस बात का उल्लेख खासतौर पर किया जिसमें कहा गया कि 'अमेरिका के साथ युद्ध में कोई भौगोलिक सीमा नहीं है।' उन्होंने कहा कि आईआरजीसी ने अपने एजेंडे में दुश्मन के नए ठिकानों की पहचान करना और नए भौगोलिक क्षेत्रों में अभियानों की योजना बनाना शामिल किया है। शनिवार को एक बयान में बताया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने सशस्त्र बलों के वरिष्ठ कमांडरों को आदेश दिया है कि 'दुश्मनों' की ओर से आने वाले किसी भी स्तर और प्रकार के खतरे का, बिना किसी भौगोलिक सीमा के, 'तत्काल और प्रभावी' जवाब दिया जाना चाहिए। ये चेतावनियां ऐसे समय में आई हैं।

ऑस्ट्रेलिया के करीब 75 फीसदी लोगों ने माना, 'एक साल में देश और बंटा'

सिडनी , एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक और सामाजिक विभाजन की खाई बढ़ती जा रही है। एक नए सर्वेक्षण में ये खुलासा हुआ है। करीब तीन-चौथाई नागरिकों ने माना कि उनका देश पिछले एक साल में पहले के मुकाबले अधिक बंट गया है। इसके साथ ही सरकार, राजनीतिक दलों और नेताओं पर जनता का भरोसा भी कमजोर हुआ है। स्वतंत्र थिंक टैंक मैकिनॉन की ने ये सर्वे कराया। सर्वेक्षण में 41.9 प्रतिशत लोगों ने इस बात से पूरी तरह सहमति जताई कि ऑस्ट्रेलिया पिछले 12 महीनों में अधिक विभाजित हुआ है, जबकि 32.5 प्रतिशत ने इससे कुछ हद तक सहमति जताई। इस तरह कुल 74.4 प्रतिशत लोगों ने देश में बढ़ते विभाजन को महसूस किया। सर्वेक्षण के मुताबिक, देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसे लेकर संतुष्ट लोगों की



संख्या भी घटी है। वर्ष 2025 में 28.8 प्रतिशत लोगों ने खुद को बहुत या कुछ हद तक संतुष्ट बताया था, लेकिन 2026 में यह आंकड़ा घटकर 26.1 प्रतिशत रह गया। वहीं, देश की दिशा को लेकर पूरी तरह असंतुष्ट लोगों की संख्या में 7.2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, जून और जुलाई में हुए इस सर्वेक्षण में 4,000 से अधिक लोगों से ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक व्यवस्था, नेताओं और संस्थानों को लेकर उनकी राय पूछी गई। सर्वेक्षण में संघीय नेताओं और राजनीतिक दलों पर भरोसे में गिरावट भी सामने आई। वर्ष 2025 में 35.9 प्रतिशत लोगों ने संघीय राजनेताओं पर पूरा भरोसा जताया था, जो 2026 में घटकर 30.5 प्रतिशत रह गया। राजनीतिक दलों पर पूरा भरोसा रखने वालों का अनुपात भी 31.2 प्रतिशत से गिरकर 24.4 प्रतिशत पर आ गया। मैकिनॉन के अंतरिम कार्यकारी अध्यक्ष और विक्टोरिया राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री जॉन थ्वेट्स ने कहा, 'ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों का लोकतंत्र की संस्थाओं पर भरोसा उस राजनीति के मुकाबले कहीं अधिक है, जो इन संस्थाओं के भीतर संचालित होती है। उन्होंने शिक्षा के आधार पर लोकतंत्र के प्रति संतुष्टि में अंतर को भी महत्वपूर्ण बताया। थ्वेट्स के अनुसार, 'विश्वविद्यालय की डिग्री या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त लोगों में लोकतंत्र से संतुष्टि का स्तर 59 प्रतिशत है, जबकि हाईस्कूल या उससे कम शिक्षा वाले लोगों में यह केवल 39.7 प्रतिशत है। सर्वेक्षण में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी असंतोष सामने आया। जब लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है।

अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल के उम्मीदवारों की बड़ी दस्तक, 57 चेहरे मंगलवार को आजमाएंगे किस्मत

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में इस बार भारतीय मूल के उम्मीदवारों की उल्लेखनीय मौजूदगी देखने को मिल रही है। ओहायो में गवर्नर पद से लेकर लॉस एंजिलिस के मेयर और मैसाचुसेट्स की सीनेट सीट तक, भारतीय मूल के 57 उम्मीदवार मंगलवार को मतदाताओं के बीच अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह संख्या अमेरिकी राजनीति में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की बढ़ती भागीदारी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी रेखांकित करती है। आईएएनएस ने देशभर से जुटाई एक लिस्ट के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। इन 57 उम्मीदवारों में एक सीनेट, 11 प्रतिनिधि सभा, तीन राज्यव्यापी पदों, 36 राज्य विधानमंडलों और छह स्थानीय पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सूची में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जिनकी भारतीय मूल की पहचान की पुष्टि हो सकी है।

इसके अलावा 15 ऐसे संभावित उम्मीदवार हैं, जिन्हें भारतीय मूल का माना जा रहा है, लेकिन पर्याप्त पुष्टि नहीं होने के कारण सूची में जगह नहीं मिली है। इन चुनावों में सबसे अधिक निगाहें ओहायो पर रहेंगी, जहां रिपब्लिकन पार्टी के विवेक रामास्वामी गवर्नर पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन को चुनौती दे रहे हैं।

रविवार को उपलब्ध फिफ्टीप्लसवन के पोलिंग औसत में एक्टन को करीब तीन अंकों की बढ़त दिखाई गई। रामास्वामी की उम्मीदवारी इसलिए भी अहम है क्योंकि वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और उनकी जीत अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल के नेताओं की स्थिति को एक



नई ऊंचाई दे सकती है। लॉस एंजिलिस में सिटी काउंसिल सदस्य नित्या रमन मौजूदा मेयर करेन बास को चुनौती दे रही हैं। यूसी बर्कले इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंटल स्टडीज और लॉस एंजिलिस टाइम्स के संयुक्त सर्वेक्षण में दोनों उम्मीदवारों को 40-40 प्रतिशत समर्थन मिला, जबकि 19 प्रतिशत मतदाता अब भी अनिर्णीत थे। यह मुकाबला भी भारतीय मूल के उम्मीदवारों की बढ़ती राजनीतिक पहुंच का एक अहम उदाहरण है। न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन उम्मीदवार सरिता कोमाटिरेड्डी अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के खिलाफ मैदान में हैं। 28 अक्टूबर को जारी सिएना सर्वेक्षण में जेम्स को 54 प्रतिशत और कोमाटिरेड्डी को 39 प्रतिशत समर्थन मिला था। मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर भी दोबारा चुनाव जीतने की कोशिश में हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से वह गवर्नर पद के उम्मीदवार के साथ चुनावी मैदान में हैं, जबकि रिपब्लिकन टिकट में डैन कॉक्स शामिल हैं। सीनेट की एकमात्र भारतीय मूल के उम्मीदवार वाली दौड़ मैसाचुसेट्स में है। यहां शिवा अय्यादुरई निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में डेमोक्रेटिक सीनेटर एड मार्की को चुनौती दे रहे हैं।

अरब पार्टियों ने याशार को समर्थन दिया; चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला

तेल अवीव, एजेंसी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू विपक्षी नेता गादी आइजनकोट के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार हैं। इजराइली मीडिया आई24 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने इस गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया है। वहीं, अरब पार्टियों जॉइंट लिस्ट और राअम ने आइजनकोट की याशार पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है। दरअसल, 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। 120 सीटों वाली संसद में सरकार बनाने के लिए 61 सीटें जरूरी हैं। नेतन्याहू की पार्टी लिकुड 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। मुख्य विपक्षी पार्टी याशार 21 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है। लिकुड के गठबंधन की 53 और याशार के गठबंधन की 48 सीटें हैं। अरब पार्टियों को 19 सीटें मिली हैं। अब अगर याशार पार्टी अरब पार्टियों के साथ गठबंधन बनाती है तो उनके पास 67 सीटें हो जाएगी।

नेतन्याहू सभी विकल्पों पर विचार कर रहे : इजराइली मीडिया द्व24 न्यूज के मुताबिक, नेतन्याहू की पार्टी लिकुड के करीबी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वे आइजनकोट के साथ गठबंधन की संभावना को भी खारिज नहीं कर रहे हैं,



जबकि सार्वजनिक रूप से वे साझा सरकार बनाने की योजना से इनकार कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, नेतन्याहू को चिंता है कि आइजनकोट अरब पार्टियों और कट्टरपंथी यहूदी धार्मिक दलों के साथ मिलकर वैकल्पिक सरकार बना सकते हैं। इससे उन्हें सत्ता से हटना पड़ सकता है।

विपक्षी दलों का समर्थन लेना : नेतन्याहू विपक्षी गठबंधन में शामिल कुछ दलों या सांसदों को अपने साथ लाने की कोशिश कर सकते हैं। विपक्ष के पास कुल 48 सीटें हैं। अगर इनमें से कुछ दल या सांसद नेतन्याहू का साथ देने को तैयार हो जाते हैं, तो वे बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों का आंकड़ा हासिल कर सकते हैं।

चुनौती- विपक्षी नेताओं ने चुनाव में नेतन्याहू को सत्ता से हटाने का वादा किया था। ऐसे में उनके लिए अब नेतन्याहू का समर्थन करना आसान नहीं होगा।

राष्ट्रीय एकता सरकार बनाना : नेतन्याहू विपक्षी नेता गादी आइजनकोट और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता सरकार बना सकते हैं। इसमें अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ आ सकती हैं। चुनौती- नेतन्याहू के कुछ सहयोगी भी इस विकल्प पर चर्चा कर चुके हैं। इससे नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का मौका मिल सकता है। लेकिन आइजनकोट पहले ही नेतन्याहू के नेतृत्व का विरोध कर चुके हैं। ऐसे में दोनों के बीच सहमति बनना मुश्किल हो सकता है।

अल्पमत सरकार बनाना : नेतन्याहू अल्पमत सरकार बनाने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसी सरकार के पास अपने गठबंधन में 61 सांसद नहीं होते। इसके बावजूद वह संसद में दूसरे दलों के समर्थन या उनके विरोध न करने के भरोसे चल सकती है। चुनौती- ऐसी सरकार को बजट पास कराने, विश्वास मत जीतने और दूसरे जरूरी फैसलों के लिए बार-बार दूसरे दलों का समर्थन जुटाना पड़ता है। इसलिए अल्पमत सरकार बनाना ही नहीं, उसे लंबे समय तक चलाना भी मुश्किल होगा। आइजनकोट अरब पार्टियों जॉइंट लिस्ट और राअम के समर्थन से सरकार बना सकते हैं। विपक्षी गठबंधन की 48 और अरब पार्टियों की 19 सीटें मिलाकर उनके पास 67 सांसदों का समर्थन है। यह बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों से ज्यादा है। आइजनकोट और अरब पार्टियों के बीच कई नैतिक मतभेद हैं। साथ ही नेतन्याहू भी इसे देश के साथ गद्दारी बता चुके हैं।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

टाइगर श्रॉफ गोलीबारी केस : करनाल से महिला गिरफ्तार, कुल 13 आरोपी हिरासत में

मुंबई, एजेंसी। मुंबई अपराध शाखा ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के मामले में हरियाणा के करनाल से एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ, मामले में अब तक कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस के अधिकारी ने बताया कि 22 वर्षीय आरोपी महिला को करनाल से पकड़ा गया। हालांकि, अपराध में उसकी विशिष्ट भूमिका का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। और महिला को मुंबई लाने की कानूनी प्रक्रिया जारी है। यह घटना 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी, जब टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल मैदान से बाहर निकल रहे थे। गोलीबारी में अभिनेता बाल-बाल बच गए थे, लेकिन उनके कार चालक और पास खड़े एक व्लॉगर घायल हो गए थे। गिरफ्तार किए गए कुल आरोपियों में अब तीन महिलाएं शामिल हैं।

चक्रवात मुरासु : ओडिशा में बारिश, 1.60 लाख लोग सुरक्षित

भुवनेश्वर, एजेंसी। आंध्रप्रदेश के तट पर गंभीर चक्रवाती तूफान मुरासु के टकराने के बाद ओडिशा के दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश दर्ज हुई है। राज्य सरकार ने किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से निपटने के लिए सभी जिलाधिकारियों को तैयार रहने का निर्देश दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा भारी बारिश और तेज हवाओं के पूर्वानुमान को देखकर दक्षिण क्षेत्र के पांच जिलों से 1.60 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और आपदा प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया गया है। ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि कोरापुट, मलकानगिरि, कंधमाल और कालाहांडी सहित कई जिलों से हल्की बारिश की सूचना है। उन्होंने कहा कि राज्य लगातार हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन ओडिशा के लिए एक बड़ी चुनौती है। मंत्री पुजारी ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम सामान्य होने तक आश्रय स्थलों में ही रहें। मुरासु के कारण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हजारों पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए हैं और मछुआरों की नौकाओं को भी नुकसान पहुंचा है।

प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था ने लोगों की स्थिति को कॉकरोच जैसा बना दिया

- हवाई किराए में बेतहाशा वृद्धि और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भड़के सौरभ दास

नई दिल्ली, एजेंसी। त्योहारी सीजन में हवाई जहाजों के किराए में हुई बेतहाशा वृद्धि के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार करने के बाद देश में बयानबाजी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नेता सौरभ दास ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि देश की मौजूदा प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था ने आम नागरिकों की स्थिति को कॉकरोच जैसा बना दिया है। दरअसल, त्योहारी सीजन में कई प्रमुख हवाई मार्गों पर टिकट की दरों में सात सौ फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया था। इस मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति ए सिंह की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए टिप्पणी की थी कि लोग हवाई यात्रा न करें। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से आहत होकर सौरभ दास ने प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुए लिखा कि आम जनता आज चौतरफा समस्याओं से घिरी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर जहरीला वायु प्रदूषण है तो सांस मत लो, सड़कों पर गड्ढे हैं तो चलो मत, पेट्रोल महंगा है तो गाड़ियां मत चलाओ, पेपर लीक हो रहे हैं तो परीक्षाएं मत दो और अगर मीडिया समाज को बांट रहा है तो टीवी देखना बंद कर दो। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में नौकरी मत खोजो, यह पूरी व्यवस्था ही नागरिकों को विवश कर रही है।

कांग्रेस के साथ जो जाता है, डूब जाता है: शिवराज सिंह चौहान

लखनऊ , एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के तहत मंगलवार को एनडीए गठबंधन ने लखनऊ में पदयात्रा निकाली। इसमें हजारों की संख्या में भाजपा और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में निकली इस पदयात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेता भी शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा।

पदयात्रा के दौरान केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने भाजपा को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि आपने हमें छेड़ दिया है। आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लोकतंत्र बचाने और अराजकता हटाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके मुताबिक, देश में 49 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष चुनावी मैदान में मुकाबला नहीं कर पाता तो झूठ फैलाकर देश को गुमराह करने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन लगातार इसी चिंता में लगा है कि नरेंद्र मोदी को कैसे हराया जाए।

इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कई राज्यों में लंबे समय से सत्ता से बाहर है। तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस की राजनीतिक जमीन कमजोर हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ऐसी पार्टी और नेता हैं, जिनके साथ जो जाता है, वह भी डूब जाता है। डूबने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि चुनाव नहीं जीत पाने के कारण कांग्रेस और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को गुंडातंत्र और लूटतंत्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने देश के बंटवारे के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन और 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने देश को बांटने का प्रयास किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन भी इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं। चौहान ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता देश को बांटने और विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत विरोधी नैरेटिव चलाने की कोशिशों को सफल नहीं होने देगा।

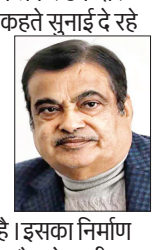


मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मृतकों, दूसरी जगह जा चुके लोगों और फर्जी व डुप्लीकेट नामों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि करीब एक करोड़ फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं। उनके मुताबिक, इससे विपक्ष परेशान है, क्योंकि वह घुसपैठियों के सहारे सरकार बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए देश के हित में काम करते हैं, जबकि इंडी गठबंधन घुसपैठियों के पक्ष में खड़ा है।

घटिया काम करने पर शर्म आनी चाहिए, गडकरी ने ठेकेदार को लगाई फटकार

- केंद्रीय मंत्री मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखने गए थे वर्धा

वर्धा, एजेंसी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह महाराष्ट्र के वर्धा जिले में घटिया सड़क निर्माण को लेकर एक ठेकेदार को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में गडकरी सड़क निर्माण में घटिया काम करने को लेकर ठेकेदार को फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं। गडकरी ठेकेदार से कहते सुनाई दे रहे हैं कि उसे ''इतना घटिया काम करने पर शर्म आनी चाहिए।'' केंद्रीय मंत्री ने ठेकेदार को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और सड़क की मरम्मत तत्काल कराने के निर्देश दिए। यह घटना रविवार की बताई जा रही है, जब गडकरी ने वर्धा जिले के सिंदी शहर में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी थी। यह परियोजना 150.42 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही है। इसका निर्माण महाराष्ट्र एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जेएनपीए) का संयुक्त उद्यम है।



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गडकरी के कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूरी तरह विकसित होने के बाद यह पार्क सड़क और रेल के जरिये माल ढुलाई को सुगम बनाएगा। इससे रसद लागत और परिवहन में लगने वाला समय कम होगा, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस परियोजना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। साथ ही इससे भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम से इतर एक स्थानीय विधायक ने वर्धा की एक सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत केंद्रीय मंत्री गडकरी से की।

नवीन पटनायक के गुमशुदा पोस्टर से ओडिशा में सियासी घमासान

भुवनेश्वर, एजेंसी। ओडिशा की राजनीति में एक नया सियासी घमासान शुरू हुआ है, जब गंजाम जिले के हिंजिली में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक नवीन पटनायक के गुमशुदा होने के पोस्टर लगे। इस घटना ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी बीजू जनता दल के बीच आरोप-प्रत्यारोप का एक नया दौर छेड़ दिया है। पोस्टर सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं.....आखिर इन पोस्टरों के पीछे कौन है और इसका असली मकसद क्या है? माना जा रहा है कि इन पोस्टरों का संबंध चक्रवात और हाल ही में आई भीषण बाढ़ के बाद हिंजिली विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सीएम पटनायक की कथित गैरमौजूदगी से है। पटनायक हिंजिली सीट से विधायक हैं, और उस समय में जब गंजाम जिले में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था और राज्य को भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा था (जिससे 13 लाख लोग प्रभावित हुए थे), उनकी क्षेत्र में अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, पोस्टर लगाने वालों की पहचान अभी तक उजागर नहीं हुई है, और न ही किसी व्यक्ति या संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जिससे इसके पीछे का वास्तविक उद्देश्य अस्पष्ट बना हुआ है। इस घटना ने भाजपा और बीजेडी के बीच राजनीतिक बयानबाजी को तेज किया है। सत्ताधारी भाजपा पूर्व सीएम पटनायक की हिंजिली में कथित अनुपस्थिति पर लगातार सवाल उठा रही है, जबकि विपक्षी बीजेडी अपने नेता का बचाव कर रही है। बीजेडी का कहना है कि पटनायक ने पार्टी नेताओं और प्रशासन के साथ समन्वय के माध्यम से राहत और सामान्य स्थिति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिलहाल, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इन गुमशुदा पोस्टरों के पीछे किसका हाथ है और इसका राजनीतिक या अन्य क्या मकसद है। लेकिन इतना तय है कि हिंजिली में लगे इन पोस्टरों ने ओडिशा की राजनीति में चक्रवात के बाद राहत कार्यों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर एक नई बहस को केंद्र में ला दिया है।

राजधानी दिल्ली में पटाखों की अवैध बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

नई दिल्ली, एजेंसी । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की अवैध बिक्री पर केंद्र सरकार से तत्काल एक्शन लेने को कह दिया है। पटाखों की बिक्री पर पाबंदी के बावजूद राजधानी के बाजारों में विभिन्न प्रकार के पटाखों की धड़ल्ले से बिक्री पर न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अखबार की खबर का संज्ञान लेकर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन किया जाए।

न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा, आज की खबर में एक तस्वीर है, जिसमें दिखाया गया है कि हमारे आदेश के बावजूद दुकानों में सब कुछ उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि बाजार में हर तरह के पटाखे उपलब्ध हैं, चाहे वे लाइसेंस प्राप्त हों या बिना लाइसेंस वाले, उन पर क्यूआर कोड हो या नहीं। न्यायालय ने इस स्थिति पर तुरंत ध्यान देने का निर्देश दिया।



सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली (7 और 8 नवंबर) पर सुबह छह से सात बजे और रात आठ से 10 बजे तक केवल हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी। हालांकि, न्यायालय ने अपने 29 अक्टूबर के आदेश में कहा था कि पूर्ण प्रतिबंध आदर्श समाधान प्रतीत होता है, लेकिन वर्तमान में उसके पास इतने आंकड़े नहीं हैं कि यह तय किया जा सके कि प्रदूषण की समस्या के लिए पूर्ण प्रतिबंध ही सबसे बेहतर विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण की समस्या पर चिंता जताकर कहा कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष गतिविधि में शामिल होने का अधिकार, भले ही उसका धार्मिक पहलू हो, पूर्ण नहीं है और यह संवैधानिक पाबंदियों से आगे नहीं हो सकता। न्यायालय ने पहले के निर्देशों को लागू करने में अधिकारियों द्वारा बरती गई ढिलाई पर नाराजगी जाहिर की है। पीठ ने स्पष्ट किया कि 9 नवंबर से पटाखों पर पहले लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित ध्वनि निषेध क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। इन क्षेत्रों को पटाखा-मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा और उनकी विधिवत निशानदेही की जाएगी।

अनिश्चितकालीन धरनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: सार्वजनिक स्थान घेरना गलत

केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जबाव

नई दिल्ली , एजेंसी। अनिश्चितकालीन धरनों पर सख्त रुख दिखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों पर दिल्ली पुलिस की सख्ती को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी समूह विरोध प्रदर्शन के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर अनिश्चित काल तक कब्जा करके नहीं बैठ सकता। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत, और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस जेवी मोहना की पीठ ने की।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ किराना कमिटी दिल्ली की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें त्यौहारों के दौरान विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान विरोध करने के अधिकार, पुलिस की कथित ज्यादतियों, सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदियों और प्रदर्शनों का व्यापार पर पड़ने वाले असर को लेकर तीखी बहस हुई।

दिल्ली व्यापारी संघों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शनों के कारण होने वाली बाधाओं पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने तर्क दिया कि विरोध-प्रदर्शनों से व्यावसायिक गतिविधियों को भारी नुकसान होता है, खासकर त्यौहारी सीज़न में हुआ नुकसान कारोबारी को ज्यादा तकलीफ देता है। वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतगी ने अदालत से कहा कि कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में दुकानें बंद रहीं, जिससे व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि अब किसी अलग तरह के समाधान (आउट-ऑफ-द-बॉक्स सॉल्यूशन) के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यह सिर्फ जंतर-मंतर पर कुछ लोगों के बैठने का मामला नहीं, बल्कि आसपास रहने वाले 50 लाख लोगों और उनके कारोबार से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

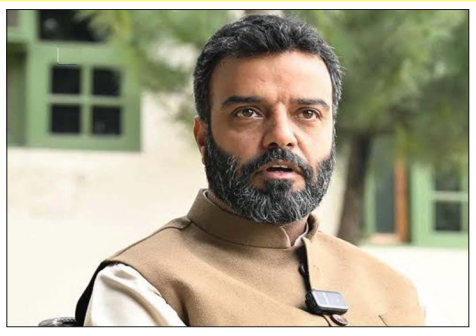
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी आदेशों को अदालत में अलग से पेश न करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई के पक्ष में तर्क दिए हैं, लेकिन संबंधित आदेश रिकॉर्ड पर नहीं हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मोदी सरकार के पांचवें हलफनामे में यह जानकारी मौजूद है, जिसमें हेबियस कॉर्पस याचिकाएं, पत्रकार, वकील और जंतर-मंतर को डीनोटिफाई करने जैसे मामले शामिल हैं। गुरुस्वामी ने इस हलफनामे की एक प्रति की मांग की। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि बंद का आह्वान करने वालों को इसके नतीजों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या विरोध-प्रदर्शन के आयोजकों को कानूनी कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया है, जिस पर रोहतगी ने उन्हें भी शामिल करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट अब इस जटिल मामले में विरोध प्रदर्शन के मौलिक अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था व आर्थिक गतिविधियों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।



उमर पर निशाना साध रुहुल्लाह मेहदी ने छोड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस

-सांसद पद से भी इस्तीफे का ऐलान कर बोले- उमर ने भाजपा के सामने घुटने टेक दिए

श्रीनगर, एजेंसी । जम्मू-कश्मीर की राजनीति में मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। श्रीनगर से लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) छोड़ने और सांसद पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। बडगाम के जहरा पार्क में अपने पिता की पुण्यतिथि पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पार्टी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला ने भाजपा के सामने घुटने टेक दिए हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं।



रुहुल्लाह मेहदी ने विशेष रूप से अनुच्छेद 370 और 35ए का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिन मुद्दों को लेकर पार्टी ने जनता से समर्थन मांगा था, उन पर अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा, वादे कुर्सियों से कहीं बड़े होते हैं। जनसभा स्थल और उनके आवास के बाहर लगाए गए बैनरों पर भी यही संदेश प्रमुखता से दिखाई दिया। एक अन्य बैनर पर चरित्र की राजनीति, सिद्धांतों की राजनीति लिखा था।

कुर्सी और सत्ता को लेकर उमर पर तंज

मुख्यमंत्री उमर पर निशाना साधते हुए मेहदी ने कहा कि कुछ लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए मतदाताओं के सामने अपनी टोपियां उतार दीं, लेकिन उन्हें जनता के वास्तविक सम्मान का अर्थ समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस कुर्सी पर आज कुछ नेता बैठे हैं, उसमें सत्ता तो है, लेकिन सम्मान नहीं है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं अपना सिर केवल सर्वशक्तिमान अल्लाह के सामने झुकाता हूं। मेरी प्रार्थना है कि मुझे कभी किसी और के सामने अपनी टोपी और पगड़ी न झुकानी पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि आमतौर पर लोग कुर्सी छिनने पर दुखी होते हैं, लेकिन वे खुद कुर्सी छोड़ने का फैसला कर रहे हैं और इससे खुश हैं।

तीन बार विधायक और पहली बार बने थे सांसद

आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने वर्ष 2002 में बडगाम विधानसभा सीट से पहली बार जीत दर्ज की थी। इसके बाद वह तीन बार विधायक चुने गए। वर्ष 2009 से 2014 तक उमर अब्दुल्ला की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने श्रीनगर सीट से जीत हासिल कर पहली बार संसद में प्रवेश किया था। उनके इस्तीफे के ऐलान से नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।

महाराष्ट्र की पांच अदालतों को बम की धमकी, गहन तलाशी के बाद झूठी निकली

मुंबई , एजेंसी । महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे, हिंगोली, बीड और नांदेड जिलों की जिला एवं सत्र अदालतों को परिसर में बम विस्फोट करने की धमकी वाले ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। इन धमकियों से राज्यभर में सुरक्षा को लेकर पुलिस ने तुरंत बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। हालांकि, विस्तृत जांच और बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) तथा श्वान दस्ते की गहन तलाशी के बाद किसी भी अदालत परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, और इन सभी धमकियों को झूठा घोषित किया गया। ठाणे शहर में अदालत की इमारत को दोपहर में ही खाली कराया गया था, क्योंकि कार्यालय को एक संदेश मिला था कि दोपहर साढ़े तीन बजे बम विस्फोट होगा। न्यायाधीशों, वकीलों और अन्य कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद, पुलिस ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। पुणे में शिवाजीनगर अदालत परिसर को भी इसी तरह के ईमेल के बाद खाली कराया गया और बीडीडीएस टीम ने संभावित संदिग्ध वस्तु की तलाश की।

राहुल गांधी से मिल, सिद्धारमैया ने स्टिंग वीडियो मामले में जारी जांच पर जाहिर की नाराजगी

नई दिल्ली, एजेंसी । कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर कथित स्टिंग वीडियो मामले में चल रही जांच पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक, सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि उनकी ही पार्टी के कुछ नेता उनकी छवि खराब करने वाले मनगढ़ंत वीडियो को बनाने में शामिल हैं।



उन्होंने पुलिस जांच के तरीके पर असंतोष जताया, उनका कहना था कि पुलिस केवल वीडियो अपलोड करने वाले की तलाश कर रही है, जबकि इसके असली निर्माताओं का पता लगाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने इस फैब्रिकेटेड वीडियो को अपनी छवि धूमिल करने की साजिश बताया और राहुल गांधी से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का आग्रह किया।

ज्ञात हो कि सितंबर में यूट्यूब पर दो वीडियो अपलोड किए गए थे, जिसमें सिद्धारमैया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मीडिया को उन पर रिपोर्टिंग से रोकने का आदेश प्राप्त किया। साथ ही, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कर जांच की मांग भी की थी।

हालिया जांच में सामने आया है कि स्टिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन दिल्ली से खरीदा गया था। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी रितेश पांडे ने बताया कि विनोद शर्मा और उन्होंने प्रज्वल प्रसाद के निर्देश पर करोल बाग से फोन खरीदा और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के सरकारी आवास पर प्रज्वल को सौंपा। दिल्ली के निवासी पांडे को 24 अक्टूबर को वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।